mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-04 अंक-192 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
12 जुलाई 2024 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित

गौतम गंभीर को ...
@ पेज 7

मोदी सरकार ने पूरी की चंद्रबाबू नायडू की इच्छा

आंध्र के लिए 60 हजार करोड़ की योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के अभी पांच ही बीते हैं। इसी बीच केंद्र ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की प्रमुख मांग को स्वीकार कर लिया है। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार में प्रमुख सहयोगी नायडू ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर राज्य में रिफाइनरी

स्थापित करने को लेकर चर्चा की थी। अब लोगों की नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जा टिकी हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि केंद्र में टीडीपी के साथ जेडीयू में अहम भूमिका में है,भले ही उसकी लोकसभा की सीटें टीडीपी के बराबर न हों। रिपोर्ट में जानकारों के हवाले से लिखा है कि रिफाइनरी के लिए तीन स्थानों पर चर्चा की गई। इनमें श्रीकाकुलम, मछलीपट्टनम और रामायपट्टनम शामिल हैं। लोगों ने बताया कि रिफाइनरी की औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में किए जाने की संभावना है। स्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया में कम से कम दो महीने लगेंगे और बजट में

अनंत-राधिका की शादी में मेहमान खाएंगे काशी की स्पेशल चाट

रिसेप्शन में बनारस गली होगी, इसमें क्षीरसागर की मिठाई, चौक का पान मिलेगा

वाराणसी (एजेंसी)। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। मुंबई में हो रही इस शादी में मेहमानों को बनारस का जायका मिलेगा। अंबानी फैमिली के खास मेहमान बनारस के चौक का मशहूर पान, गोदौलिया की स्पेशल चाट और क्षीर सागर की मिठाइयों का लुत्फ उठाएंगे। 13 जुलाई को रिसेप्शन में बनारस गली नाम की एक गैलरी होगी। गैलरी में 4-4 वैराइटी की चाट, मिठाई और पान होगा। वाराणसी के 45 कारीगरों की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। 15 दिन पहले नीता अंबानी वाराणसी में थीं। उन्होंने बाबा विश्वनाथ को बेटे अनंत की शादी का कार्ड चढ़ाया। उसके बाद गोदौलिया पर आकर काशी चाट का स्वाद चखा। स्वाद भाया तो उन्होंने ऑर्डर दिया। दुकानदार से कह दिया कि शादी में आप लोग मुंबई आएं। वहां पर इस चाट का स्टॉल लगाएं। इसके बाद काशी चाट और अंबानी टीम की ओर से लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था। 10 दिन के बाद बजट फाइनल हुआ और अब काशी चाट का स्टॉल लगाने की मंजूरी मिल गई।

संक्षिप्त समाचार

एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी...

फिर शुरू होगा आंदोलन

नई दिल्ली (एजेंसी)। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने घोषणा की है कि वे अपनी लंबित मांगों के लिए फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और किसान कर्ज माफी शामिल हैं। एसकेएम के नेताओं ने कहा है कि सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया है और उन्हें मजबूरन फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है ताकि किसान समुदाय को राहत मिल सके। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी चाहते हैं।

भारतवंशी ने गीता पर हाथ रखकर ली सांसदी की शपथ

- 27 साल की शिवानी लीस्टर ईस्ट से सांसद

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन की संसद में बुधवार को भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवद गीता पर हाथ रख कर सांसदी की शपथ ली। उन्होंने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से लीस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज की है। शिवानी ने

लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को 4 हजार से ज्यादा वोटों से हराया है। लीस्टर ईस्ट को लेबर पार्टी का गढ़ माना जाता है। शिवानी ने यहां 37 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी को जीत दिलाई है। शपथ लेने के बाद शिवानी ने बताया गीता के साथ शपथ लेना अच्छा लगा।

शीना बोरा हत्याकांड

गायब हड्डियां सीबीआई के ऑफिस में ही मिलीं

मुंबई (एजेंसी)। शीना बोरा हत्याकांड को लेकर 10 जुलाई को मुंबई की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि अप्रैल में गायब हुई हड्डियां सीबीआई के दिल्ली वाले ऑफिस के मालखाने में मिल गई

हैं। यह खुलासा उस दिन हुआ, जब कोर्ट को मिले एक ईमेल में आरोप लगाया गया कि शीना की हड्डियां गायब नहीं हुईं, बल्कि वे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास हैं, जिसने उनकी जांच की थी और जो गवाह के तौर पर अदालत के सामने गवाही दे रहा था। ईमेल में आरोप लगाया गया है कि इस गवाह ने अचानक बहुत संपत्ति अर्जित कर ली है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को फोरेंसिक विशेषज्ञ का भाई बताया। इन हड्डियों के न मिलने से पिछले महीने फोरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही को रोक दिया गया था। इन अवशेषों को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा।

पुतिन-मोदी की 'जादू की झप्पी' से चीन को लगी मिर्ची

अमरीका भी टेंशन में,भारत के बढ़ते कद से हो रहा परेशान

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रूस यात्रा ने न केवल भारत-रूस संबंधों को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़ी चर्चा को जन्म दिया। पांच साल बाद रूस की धरती पर कदम रखते ही मोदी का स्वागत गर्मजोशी और शाही तरीके से हुआ, जो दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। यह यात्रा खास इसलिए भी रही क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह मोदी की पहली मॉस्को यात्रा थी, जिस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की खास नजर थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की शान में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, जो दोनों देशों के बीच सम्मान और विश्वास को और भी मजबूत बनाता है। पुतिन और मोदी का गर्मजोशी से गले मिलना कई मायनों में महत्वपूर्ण था।

उनका गले मिलना यह संकेत था कि रूस को पश्चिमी दबाव के संतुलन के लिए केवल चीन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह पश्चिम के लिए एक स्पष्ट संदेश भी था कि भारत किसी एक खेमे में बंधकर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बाद यह चर्चा उठी कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान के गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वापस ला दिया है। गुटनिरपेक्षता की इस नीति का उद्देश्य था कि भारत किसी भी बड़े शक्ति गुट का हिस्सा बने बिना अपनी स्वतंत्र नीति अपनाए। इस यात्रा ने एक बार फिर से इस नीति को महत्व दिया।

'नीट' मामले में सीबीआई के हाथ लगी 'बड़ी मछली'

झारखंड से रॉकी को किया गिरतार,10 दिन की मिली रिमांड

पटना (एजेंसी)। नीट पेपर लीक मामले में जिस शख्स की तलाश सीबीआई को सबसे ज्यादा थी। आखिरकार उस आरोपी रॉकी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। जिसे आज पटना कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिनों की रिमांड दी है। इससे पहले रॉकी के भारत छोड़ नेपाल भागने की खबर थी। जिसे आज सीबीआई ने आज धर दबोचा है। दरअसल रॉकी ही वो कड़ी है।

जिसकी मदद से मुख्य सेटर तक सीबीआई पहुंच सकती है। जिसकी भूमिका प्रश्न-पत्र को आउट कराने में सबसे अहम है। रॉकी मूलरूप से बिहार के नवादा का रहने वाला है। उसका वास्तविक नाम राकेश है। पिछले कुछ सालों से वह झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। सीबीआई टीम ने चार मुख्य आरोपियों चिंटू, मुकेश, मनीष और आशुतोष को सात दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की। जिसमें रॉकी से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे बताया जा रहा है कि रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। चिंटू से खासतौर से रॉकी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। चिंटू से एक और संजीव मुखिया को लेकर भी जानकारी ली जा रही है। क्योंकि वह संजीव की भांजी का पति है। संजीव के नेपाल भागने की सूचना मिल रही है।

टल गई सुनवाई,छात्रों को और करना होगा इंतजार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में हृश्वश्वञ्-त्र मामले को लेकर आज होने वाली सुनवाई अगली तारीख तक टाल दी गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इससे पहले आज सीबीआई ने कोर्ट में बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ऐसे में सभी छात्रों की निगाहें शीर्ष अदालत के फैसले पर टिकी हैं कि क्या हृश्वश्वञ्-त्र परीक्षा

कैंसिल होगी और फिर से एग्जाम होंगे? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार, हृञ्ज और ष्टक्चढ्ढ की ओर से एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें कथित पेपर लीक मामले की दोबारा परीक्षा कराने और उचित जांच की मांग की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र और हृञ्ज ने 5 मई को आयोजित परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया है।

अभी नहीं कम हो रही केजरीवाल की मुश्किलें

- सीबीआई के बाद अब ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने भेजा वारंट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को पेशी का वारंट जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर सातवीं चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। सीएम केजरीवाल शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें हाल ही में सीबीआई ने भी दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्तार करके पूछताछ की थी। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। यह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पीएमएलए मामले में उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के कुछ घंटों बाद हुआ। अदालत की अनुमति के बाद, सीबीआई ने 26 जून को कोर्ट में केजरीवाल से पूछताछ की और फिर मामले में उन्हें औपचारिक रूप

से गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में, उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 01 जून तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी।

ट्रेनी आईएएस ने हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम बताया

- बोलीं-देखने में भी दिक्कत, मेडिकल टेस्ट से 6 बार इनकार, अब सिलेक्शन पर सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र की एक ट्रेनी ढ्ढस्-अफसर पूजा खेडकर काफी चर्चा में हैं। पूजा ने संघ लोक सेवा आयोग (क्कस्ष्ट) को दिए एक हलफनामे में दावा किया है कि वह मानसिक रूप से अक्षम हैं और उन्हें देखने में भी दिक्कत होती है। ह्वष्ठञ्जङ्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पूजा ने मेडिकल टेस्ट देने से 6 बार मना किया था। मेडिकल टेस्ट देना जरूरी होता है। अपुष्ट

रिपोर्ट्स बताती हैं कि पूजा का पहला मेडिकल टेस्ट दिल्ली ,ढ्ढढ्ढरूस् में अप्रैल 2022 में शेड्यूल हुआ था। उन्होंने कोविड पॉजिटिव होने का हवाला देकर इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि जब पूजा ने एग्जाम में शामिल होने से मना कर दिया था तो फिर सिलेक्शन क्यों और कैसे हुआ? पूजा 2023 की ढ्ढस् अफसर हैं और अहमदनगर की रहने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पूजा ने जुलाई और अगस्त में हुए टेस्ट शेड्यूल में भी शामिल होने से मना कर दिया था। सितंबर में हुए शेड्यूल टेस्ट को भी उन्होंने आधा अटेंड किया था। यही नहीं, पूजा स्रूक्रढ्ढ टेस्ट में भी शामिल नहीं हुई थीं। इस टेस्ट में इस बात की जांच होती है कि आप देख सकते हैं या नहीं। वहीं, पूजा ने खुद को पिछड़ा वर्ग (ह्रक्चष्ट) का बताया था।

बजट से पहले नीतिश की पार्टी ने चल दी 'स्पेशल' चाल

राजद चीफ लालू यादव की 'अगस्त' वाली बात होगी सच!

पटना (एजेंसी)। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, इसको लेकर एक बार फिर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर स्पेशल स्टेटस संभव नहीं है तो विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर हमलोग आशान्वित हैं। उम्मीद करते हैं कि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। बजट से पहले जेडीयू के स्पेशल चाल से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू यादव की भविष्यवाणी सच होगी। लालू ने कहा था कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। अशोक चौधरी ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना राज्य के लिए एक तरह से पैकेज की तरह ही होगा। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार 10 प्रतिशत का योगदान करती थी और 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब यह अनुपात 50-50 हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि उसका योगदान कम हो और इसके लिए केंद्र सरकार को एक नया फॉर्मूला तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की मांग जरूर करेंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं रहीं, तो हमें कम से कम विशेष पैकेज तो मिलना ही चाहिए। वहीं, जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देने पर विचार करना चाहिए।

इसरो के वैज्ञानिकों को रामसेतु पर मिली बड़ी सफलता

- तैयार किया रिजॉल्यूशन वाला मैप,स्पेस एजेंसी नासा की ली मदद

नई दिल्ली (एजेंसी)। रामायण में रामसेतु का जिक्र आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। इसे भगवान राम की वानर सेना ने रामेश्वरम द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच बनाया था, ताकि रावण की लंका से माता सीता को वापस लाया जा सके। इसी रामसेतु को लेकर अब इसरो के वैज्ञानिकों को बड़ी

सफलता मिली है। खुशखबरी दी गई है कि वैज्ञानिकों ने रामसेतु, जिसको कि एडम ब्रिज भी कहा जाता है, उसका एक डिटेल्ड मैप तैयार किया है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी स्पेस रिसर्च संस्थान नासा की सैटेलाइट्स के डेटा का इस्तेमाल किया है। रिसर्चर्स ने ढ्ढष्टश्वस्ड्डह्ल-2 के अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2023 तक के डेटा का उपयोग करते हुए जलमग्न सेतु की पूरी लंबाई का 10 मीटर रिजॉल्यूशन वाला मैप तैयार किया है।

सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से हटे जस्टिस संजय कुमार

निजी कारणों का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब 15 जुलाई को सुनवाई करेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार (11 जुलाई) को ्रक्क नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। अब 15 जुलाई को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।

संक्षिप्त समाचार

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सरल आनलाइन प्रक्रिया

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। आम नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2021 के पूर्व उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से जारी किए जाने का प्रावधान था। मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड चिकित्सक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनआईसी के सारथी पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ज्यादा सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे।

बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने की अपील

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के लिये छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना वर्ष 2014 में प्रारम्भ की है। निदेशक डाक सेवाएं भोपाल ने बताया कि इस योजना के तहत पोस्ट आफिस में मात्र 250 रूपये से खाता खुलवाया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम जमा राशि पहले 1000 रूपये थी, जिसे घटाकर अब 250 रूपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत खाते में एक वित्तिय वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रूपये जमा किये जा सकते है। किसी भी परिवार की अधिकतम 2 बेटियां इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकती है। बेटी जुड़वा होने की स्थिति में अधिकतम 3 बेटी इस योजना के तहत लाभ ले सकती है लेकिन इसके लिये जन्म संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। सुकन्या समृद्धि के खाते में खाता खुलने के अधिकतम 15 साल तक राशि जमा करानी होती है। बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद खाते में जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है। यह खाता बालिका की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मेच्योर होता है। यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होता है तो शादी की तारीख के बाद कभी भी खाता बंद कर पूरी राशि ब्याज सहित निकाली जा सकती है। इस योजना के तहत खाता खुलवाने वाले को आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत छूट भी मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में 7.6 प्रतिशत ब्याज मिलता है, जो अन्य बचत खातों की तुलना में काफी अधिक है। खाता खुलवाने के लिये लड़की का जन्म प्रमाण-पत्र, माता पिता का फोटो पहचान पत्र तथा बच्चे और माता पिता की फोटो लेकर पोस्ट आफिस में जाना होगा।

सहकारी समितियों का पंजीयन केवल ऑनलाइन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। जिले में सहकारी समितियों का पंजीयन अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि समितियों के पंजीयन के लिए विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने के लिए आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑनलाईन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉग इन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने के लिए आधार से लिंक मोबाईल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा। प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जायेगा। अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करेगा। आधार नंबर से वर्चुएल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा। विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।

वनाधिकार पट्टा धारकों को मिले पीएम आवास का लाभ-राज्यपाल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि वन अधिकार पट्टा धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समुचित रूप से मिले। पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अनिवार्यतः लाभ दिया जायें। श्री पटेल ने उक्त निर्देश वन विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। राजभवन में आयोजित बैठक में वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर और अपर मुख्य सचिव वन विभाग श्री अशोक कुमार बर्णवाल मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने बैठक में वन मित्र पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोर्टल को आवेदक फ्रेंडली और पात्र हितग्राहियों की सहूलियत का विशेष ध्यान रख जाए। उन्होंने वन अधिकार पट्टा धारकों के लिए खेल मैदान, हाट बाज़ार, मढ़ई-मेले और श्मशान घाट की व्यवस्था

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जनजाति समुदाय को पीएम जनमन योजना के विभिन्न घटकों को संयोजित कर प्राथमिकता से लाभान्वित करें। उन्होंने बैठक में पीव्हीटीजी वनधन केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वन अपराध में जनजाति व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण कर त्वरित निराकरण के लिये मानिटरिंग की जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने बैठक में लघु वनोपज संग्रहण अधिकार, वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन, नवीन ग्राम सभाओं के गठन के पश्चात उनके नजरी नक्शे और सीमांकन की स्थिति, तेंदू-पत्ता संग्रहण, गौण वनोपज का संग्रहण एवं प्रबंधन तथा विपणन, वनोपज की खरीदी एवं बिक्री, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय-विक्रय, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के गठन, गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु सूक्ष्म प्रबंध योजना, खनिज स्वामित्व को लेकर ग्राम सभाओ की स्थिति, आदि के विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा कर निर्देश दिए। वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि लघु वनोपज संग्रहण की नीतियों में जनजातीय वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बैठक में जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण और गौण वनोपज के संग्रहण, प्रबंधन और विपणन में पेसा एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के प्रयासों को और अधिक विस्तारित किया जाए।

पेसा प्रावधानों के आधार पर वनोपज संग्रहण, प्रबंधन और विपणन को और अधिक हितग्राही मूलक बनाने के संबंध में चिंतन भी किया जाए। बैठक में राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मुकेशचंद गुप्ता, सचिव वन श्री असीम श्रीवास्तव, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ के सदस्य उपस्थित रहे।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने मध्यप्रदेश के जलजीवन मिशन की समीक्षा की।

बैठक में मध्यप्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके भी उपस्थित थीं। मंत्री श्रीमती उईके ने बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रशासनिक अमला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षाओं के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने और जल संरक्षण की दिशा में कटिबद्ध है। बैठक में सचिव श्री पी. नरहरि ने प्रदेश में जल जीवन मिशन में किए गए कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके ने जल जीवन मिशन की सफलता की कहानियों पर केन्द्रित पुस्तक का विमोचन भी किया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बुधवार को मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा की। मंत्री श्री काश्यप ने हाल ही में पंजीकृत स्टार्टअप्स की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमएसएमई वेबसाइट पोर्टल में सुधार किया जाए ताकि उद्यमियों को बेहतर और सरल सेवाएं मिल सकें। मंत्री श्री काश्यप ने इनक्यूबेटर्स की कार्य प्रणाली की भी समीक्षा की। अधिकारियों एवं एक्सपर्ट्स को निर्देश दिए कि वे जिलों में जाकर वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार स्टार्टअप योजनाएं तैयार करें। इसके अलावा, कॉलेज के छात्रों को स्टार्टअप्स

की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाने के भी निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक युवा उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

बैठक में वित्तीय सहायता पर भी चर्चा हुई। श्री काश्यप ने लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द राज्य स्तरीय वित्तीय सहायता समिति की बैठक में क्लियर करने के निर्देश दिए। सीड फण्ड की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मंत्री श्री काश्यप ने अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सक्रियता से कार्य करने को कहा है। जिससे राज्य में उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को हर संभव समर्थन करेगी एवं राज्य में स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये तेजी से हो रहे है प्रयास

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी समिति परिसर में सचिव मछुआ कल्याण और मस्त्य विकास विभाग डॉ. नवनीत मोहन कोठारी की उपस्थिति में मछुआ दिवस मनाया गया। प्रति वर्ष 10 जुलाई 1957 को डॉ. हीरालाल चौधरी द्वारा सीफा भुवनेश्वर में पहली बार सफर मछली का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया गया था। यह एक ऐसा उल्लेखनीय कार्य था, जिससे मछली पालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। इस क्रांति को नीली क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति से देश में लाखों लोगों को मछली पालन से जोड़ा गया है। इस उपलब्धि के लिये देश में हर साल 10 जुलाई को मछुआ दिवस मनाया जाता है। मछुआ कलयाण सचिव डॉ. कोठारी ने कहा कि प्रदेश में मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास के लिये ठोस प्रयास किये जा रहे है। अधिक से अधिक मछुआरों को सहकारी समिति के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में 3 लाख 42 हजार

मीट्रिक टन मत्स्योत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि मछुआरों की सहकारी समितियों से आगामी वर्ष में प्रदेश में 3 लाख 90 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।

कार्यक्रम में संचालक मत्स्य उद्योग श्री भरत सिंह और मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती ज्योति टोप्पो ने भी संबोधित किया। श्रीमती ज्योति टोप्पो मुख्य महाप्रबंधक मत्स्य महासंघ द्वारा सभी मछुआ भाई बहनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि कोई भी कार्य बिना लक्ष्य के पूरा नहीं हो सकता हमें लक्ष्य पर ध्यान रखना होता है। तालाबों से मत्स्य उत्पादन में मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य लगातार प्रगति कर रहे हैं श्रीमती टोप्पो द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी मछुआ भाई बहनों की सराहना की।

सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये कैरियर मार्गदर्शन होगा। इसके लिये नोडल शिक्षकों को वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। वर्तमान में विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट के लिये यू-रिपोर्ट के माध्यम से लाईव-11 कोर्स् का उपयोग प्रदेश के सीएम राइज और पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थी उपयोग कर रहे हैं। कैरियर मार्गदर्शन का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय की समझ एवं कैरियर के महत्व को समझाना और कक्षा 10वीं के बाद विषय संबंधित निर्णय लेने में सहायक बनाना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कैरियर के बारे में जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आगे चलकर स्वयं का व्यवसाय और उद्यमशीलता के बारे में जानकारी दी जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि इसके लिये वे संबंधित विद्यालयों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाये। वेबिनार में विद्यार्थी अपनी शंका का समाधान और जिज्ञासा चैट में प्रश्न कर सकते हैं। प्रदेश के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन ऐसे विद्यालयों में किया जायेगा जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है। प्रदेश में 4473 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। जहाँ कक्षा एक से 12, एक से 10वीं, एक से 8वीं और एक से पाँचवी के विद्यालय हैं, जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है। ऐसे विद्यालयों में नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 का संचालन किया जायेगा। इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी को शाला सत्यापन के साथ इनके प्रमाणीकरण के लिये भी कहा गया है।

आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए पौध-रोपण अत्यंत जरूरी-ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाए जाने का कार्य तेजी से जारी है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने महू के समीप भाटखेड़ी में हेमा बुधवार को रेंज परिसर में पौध-रोपण किया। इस अवसर पर एकत्रित ग्रामीणों ने 25 हजार पौधे लगाए। ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में साढे 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि इन पौधों की सुरक्षा करें और इन्हें पेड़ बनाए। उन्होंने कहा कि पौधा है तो जल है, जल है तो कल है, जीवन के लिए भी पेड़ अत्यंत जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित, स्वस्थ तथा बेहतर जीवन के लिए भी पेड़ों की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पौध-रोपण का यह जन आंदोलन आगे भी निरंतर जारी रहेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर जिले में 51 लाख पौधे लगाए जाने का कार्य तेजी से जारी है। इस महत्वाकांक्षी अभियान में समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी मिल रही है। अब हमने निर्णय लिया है कि इस तरह का अभियान हर वर्ष चलाया जाएगा।

इंदौर को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरती मां की सेवा करना हमारा फर्ज है। हरियाली धरती माता का श्रृंगार है। हमें आगे आकर धरती मां को श्रृंगारित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना होंगे। उन्होंने कहा कि धरती पर बढ़ते तापमान और वर्षा की कमी पौधे नहीं लगाई जाने से हो रही है। पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए पौधे लगाए जाएं। कार्यक्रम को सांसद सुश्री कविता पाटीदार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुश्री पाटीदार, पूर्व विधायक श्री अंतर सिंह दरबार, श्री चिंटू वर्मा, श्री सतीश मालवीय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामकरण भाभर, श्री मनोज ठाकुर सहित अन्य जन-प्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद थे। ग्रामीण विकास मंत्री ने भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय महू में किया पौध-रोपण ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने बुधवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान में स्व. भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय महू में पौध-रोपण किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर और जन-प्रतिनिधिगण मौजूद थे। मंत्री श्री पटेल ने कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों एवं जन-प्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलायी। विधायक सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि जितने भी पौधे लगाए जा रहे हैं, उन्हें पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लगाये गये पौधे को बड़ा करने का दायित्व भी लें और बड़ा होने तक उनका संरक्षण करें।

35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वर्ष में एक बार स्वास्थ्य की जाँच करायें- उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में स्वस्थ रीवा, समृद्ध रीवा अभियान की समीक्षा की। उन्होंने जिले में आयोजित विशेष शिविरों में चिन्हित रोगियों के उपचार का फॉलोअप लिया। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जाँच केन्द्रों में संबंधित की रिपोर्ट को नियत समय पर उपलब्ध करायें।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के आमजनों के स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थित रूप से चलें इसकी ज़िम्मेदारी संबंधित बीएमओ तथा सीमएचओ की

है। उन्होंने सगरा, भिटवा, भटलो में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की तथा कमियों को दूर करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिले के 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वर्ष में एक बार अपने स्वास्थ्य की जाँच कराने के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाएं। ताकि बीमारियों का समय से चिन्हांकन कर समुचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने शासकीय स्वास्थ्य कर्मियों व जाँच के लिए नियुक्त एजेंसियों के प्रतिनधियों के बीच समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि कैंसर जाँच शिविर में जिन व्यक्तियों में कैंसर के लक्षण पाए गए थे उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल की टीम द्वारा आगामी दिनों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जनपद, तहसील एवं जिले के बड़े बाजार वाले क्षेत्रों में शिविर आयोजन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का कैंसर की जाँच सुगमता से कराई जा सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ रीवा और समृद्ध रीवा का संकल्प लेकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच का अभियान अनवरत चलता रहेगा और हम रीवा को स्वस्थ रीवा बनाने का संकल्प पूरा करेंगे और अन्य जिले भी इसका अनुसरण करके स्वस्थ मध्यप्रदेश बनायेंगे।

पंचायत राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवारों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की

पीड़ित परिवारों को मिलेगी 4 लाख-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता, रेडक्रास से दिये गये 25 हजार रुपये

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने सूरत दुर्घटना के मृतको के घर जाकर उनके परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। राज्य मंत्री ने कहा कि दुर्घटना में असमय अपने प्रियजनों को खो देना बहुत कष्टकारी होता है। दुःख की इस घड़ी में सरकार आपके साथ है तथा जीवन को सुव्यवस्थित करने में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होने जिला रेडक्रास सोसायटी के माध्यम से मृतकों के निकटतम परिजन को 25 हजार-25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होने कहा कि संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रीमिकों के निकटतम परिजन को योजना के माध्यम से तथा अन्य को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 4 लाख-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उनके खातों में प्रदान की जाएगी। राज्य मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ित परिवारों को अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राथमिकता पर दिलाना सुनिश्चित करायें।

इस अवसर पर पंचायत राज्य मंत्री ने ग्रामीणजनों की समस्याएं भी सुनी तथा अधिकारियों को तत्परता से समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। ग्राम दियाडोल के निवासियों के पेयजल संबंधी समस्या का पंचायत राज्य मंत्री ने प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होने सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने पीड़ित परिवारों का ढाडस बढ़ाया। उन्होने कहा कि इस दुर्घटना के विषय में जानकारी प्राप्त होते ही उन्होने गुजरात सरकार से हर संभव सहायता के लिए संपर्क किया था। प्रयासों के बावजूद अमूल्य जिन्दगियों को नहीं बचाया जा सका। उन्होने कहा कि इस कठिन समय में वह उनके साथ खड़े हैं किसी भी समस्या के लिए वह उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

अपर कलेक्टर राजेश शाही ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आर्थिक सहायता के लिए सूरत प्रशासन के साथ भी वह लगातार संपर्क में हैं।

गत सप्ताह सचिन जीआईडीसी सिद्धि गणेश पाली गांव जिला सूरत गुजरात में ईमारत ढहने के हुए हादसे में सीधी जिले के पांच श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। पंचायत राज्य मंत्री तथा सांसद ने कोटमा टोला मझौली के मृतक अभिलाष केवट पिता छोटेलाल केवट, ग्राम दियाडोल के मृतक शिवपूजन केवट एवं प्रवेश केवट पिता शौखीलाल केवट तथा ग्राम परासी के मृतक हीरामणि केवट एवं लालजी केवट पिता बंभोली केवट के घर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की और शोक संवेदना व्यक्त की। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह कुशराम सहित जनप्रतिनिधिगण, उपखण्ड अधिकारी मझौली आर पी त्रिपाठी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रोशनी ठाकुर सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आजीविका मिशन द्वारा आर-सेटी सीधी से कराया जायेगा प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जिले के जिला अग्रणी बैंक के माध्यम से स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) संचालित किया जाता है, जिसका वित्त पोषण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किया जाता है। सीधी जिले में यह कार्य यूनियन बैंक के माध्यम से संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसके एक वरिष्ठ शाखा प्रबंधक स्तर के अधिकारी निर्देशक के रूप में कार्य करते है।

वित्त वर्ष 2024-25 हेतु आर-सेटी सीधी में 1000 ग्रामीण गरीब स्व सहायता समूहों के सदस्यों एवं उनके परिवारजन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण जैसे कि - बैंक मित्र, घरेलु विद्युत उपकरण, सेवा उद्यमी, महिला टेलर, कृषि उद्यमी, फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी, कम्प्युटराईज एकाउंटिंग, कस्ट्यूम ज्वेलर उद्यमी, जूट प्रोडक्ट उद्यमी, बम्बू केन क्राफ्ट मेकिंग, ब्यूटीपार्लर मैनेजमेन्ट, ईडीपी फर माईक्रो इन्टरप्राईजेज, शॉपकीपर, पेपर कवर एनवलप एण्ड फाईल मेकिंग, प्लम्बिंग एवं सेनेटरी वर्क, पापड़-आचार व मसाला मेकिंग, डेयरी फार्मिंग विषय पर आयोजित किए जाने है। जिस हेतु आयु 18 से 40 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता विषय अनुसार (5वीं, 8वीं, 10वीं व 12वीं) इच्छुक स्व सहायता समूह सदस्य एवं उनके परिजन आर-सेटी पुरानी सीधी (मड़वास रोड), चन्द्रा पेट्रोल पम्प के पास पहुँचकर निर्देशक शिवेन्द्र चौधरी, मो.नं. - 9415763082 व सीनियर फैकल्टी, उमाशंकर जायसवाल, मो.नं. - 9827374606 पर संपर्क कर सकते है। साथ ही विकासखण्ड स्तर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में संपर्क कर प्रशिक्षण हेतु पंजीयन करा सकते है। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क एवं प्रशिक्षण उपरान्त गतिविधि संचालन हेतु उचित बैंक ऋण भी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

बसों की चेकिंग कर एक लाख 70 हजार रुपये से अधिक शमन शुल्क वसूल की गई

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला परिवहन अधिकारी आशुतोष सिंह ने जानकारी देकर बताया है कि दिनांक 07.07.2024 से 09.07.2024 के मध्य अभियान चलाकर यात्री बसों की चेकिंग की गई जिसमें एपी53च0420 को बिना परमिट व 1 अन्य एपी5317च413 को परमिट शर्तों के उल्लंघन में जप्त कर 1 लाख 70 हजार का शमन शुल्क वसूल किया गया। उक्त के अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम की विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर भी 36 हजार रूपये के चालान काटे गये। बस मालिकों को निर्देशित किया गया कि वाहनों के दस्तावेज पूर्ण कर बस संचालित करें। यात्रियों से ज्यादा किराया लिये जाने पर भी 5 हजार रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया। उक्त के अतिरिक्त स्कूल बस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पूर्ण कर बस संचालित किये जाने हेतु भी जांच की गई।

प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस का भव्य उद्घाटन समारोह 14 जुलाई को

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों के 55 प्रधानमंत्री कॉलेज आफएक्सीलेंस का उद्घाटन गृह मंत्री भारत सरकार के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में अटल बिहारी वाजपेई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर से लाइव किया जाएगा। जिसका सीधा प्रसारण बड़ी एलईडी स्क्रीन पर महाविद्यालय में आयोजित समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं छात्र-छात्राओं को दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी परिवारातकोत्तर महाविद्यालय सीधी में भी इंदौर से होने वाले सीधे प्रसारण से 1 घंटे पूर्व महाविद्यालय में कार्यक्र म आयोजित होगा, जिसका स्वरूप इंदौर में होने वाले सीधे प्रसारण के समान ही होगा। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय में उद्घाटन की तैयारी महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा की जा रही है। महाविद्यालय के कार्यक्र म को भी टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से इंदौर से देखा जा सकेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पी. के. सिंह ने कार्यक्र म को सफल बनाने एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मध्य प्रचार प्रसार के लिए महाविद्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया। साथ ही समाज के अग्रणी लोगों एवं महाविद्यालय में अध्यनरत बीए/बीएससी/बीकॉम एवं परिवारातकोत्तर कक्षाओं के नवप्रवेशी एवं विगत सत्र के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में पहुंचकर कार्यक्र म को सफल बनाएं। सत्र 2024-25 के लिए नव प्रवेशित विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि 14 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 1 बजे के पूर्व कार्यक्र म में महाविद्यालय में आवश्यक रूप से पहुंचने का कष्ट करें।

छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। बीड़ी संगठन रीवा के कोषाध्यक्ष मोहम्मद जलील ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति मे बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के बीड़ी चूना पत्थर एवं डोलोमाईट व लौह-मैग्नीज - क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत पुत्र-पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजना के तहत कक्षा-1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति की राशि रुपये 1000 से अधिकतम 25000 रु तक स्वीकृत की जाती है। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र-छात्राओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 30 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। जिसकी अंतिम तिथि प्री-मेट्रिक हेतु 31 अगस्त 2024 एंव पोस्ट मेट्रिक हेतु 31 अक्टूबर निश्चित की गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए ओटीआर यानि वन टाइम रजिस्ट्रेशन व फेस ओथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है आवेदन की पात्रता व संबधित अन्य जानकारी एंव शर्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन करने के पश्चात अपने शिक्षण संस्थान में संपर्क कर अपने आवेदन को स्कॉलरशिप पोर्टल-स्कॉलरशिप डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से ही सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।

पुलिस परेड ग्राउंड सीधी में ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित

पंचायत राज्य मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लगाए पौधे

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान अंतर्गत पुलिस परेड ग्राउंड सीधी में आयोजित पौधरोपण कार्यक्र म में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ राजेश मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार पाण्डेय, उप पुलिस महानिरीक्षक साकेत पाण्डेय, कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉ. रविन्द्र वर्मा, वनमंडलाधिकारी क्षितिज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों तथा अधिकारियों ने स्कूली छात्रों के साथ पौधे रोपित किए तथा प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के संकल्प लिया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए पंचायत राज्य मंत्री श्रीमती सिंह ने कहा कि ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रकृति की सेवा और मां के प्रति सम्मान का अनुकरणीय भाव है। सीधी जिले में इस अभियान को जन जनअभियान बनाएं। उन्होंने कहा कि सीधी जिले में अत्यधिक क्षेत्र जंगल का है जिसमें पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए हम सबको संकल्पित होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी पेड़ लगाने के काम कर रहे हैं। हमें इस अभियान में उनके साथ सहभागिता करनी चाहिए। पंचायत राज्य मंत्री ने इस कार्यक्र म में स्कूली छात्रों की सहभागिता की सराहना की तथा कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक युवा पीढ़ी को जोड़ें। उनके मन में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के भाव जागृत करें। उन्होंने सभी से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम के अभियान का संकल्प हर व्यक्ति ले और लक्ष्य तक पहुंचाए। सभी एक पेड़ अपने मां के नाम से जरूर लगाएं।

सांसद डॉ. मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा वातावरण का परिशोधन के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मां के नाम से एक पौधा अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। पौधे के बड़े होने तक देखरेख भी करनी चाहिए। भीषण गर्मी से निजात पाने एवं एसी से मुक्ति पाने के लिए इस अभियान को सफल बनाने व प्रकृति के साथ सहयोग की भावना के साथ सभी को पौधे लगाने चाहिए। उन्होने कहा कि केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं है उनकी देखभाल भी जरूरी है। वृक्षों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वृक्षों से ही हमें प्राणवायु मिलती है। अनेक प्रकार की औषधियां, फल, फूल व छाया प्राप्त करते हैं। भावी पीढ़ी को यदि स्वस्थ, खुशहाल रखनी है तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना है तो हमें अधिक से अधिक पौधे रोपना होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री पाण्डेय ने आमजन को देश में पड़ रही भीषण गर्मी के प्रभाव को कम करने हेतु प्रत्येक परिवार को कम से कम 05-05 पौधे लगाये जाने तथा उनको संरक्षित करने का संदेश दिया। ताकि आगे आने वाले समय में हम अपने पर्यावरण को बचा सकें एवं आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सके। उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा क्षेत्र साकेत पाण्डेय ने कहा कि हम सब देख रहे है कि प्रत्येक वर्ष तापमान में वृद्धि हो रही है जिसका मुख्य कारण पर्यावरण में असंतुलन है इसलिये हम सबकी जबावदेही बनती है कि हम कम से कम एक वृक्ष लगाये तथा आने वाली पीढ़ी को भी इस अभियान से जोड़ें। पुलिस अधीक्षक डॉ वर्मा ने कहा कि एक पेड़ मॉ के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे वातावरण को स्वच्छ व शुद्ध रखना है तथा प्रकृति के प्रति सकारात्मक रवैये को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना है ताकि बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण अशुद्ध होते वातावरण से आने वाली पीढ़ी के लिए इसे अनुकूल बनाया जा सके।

अभियान के तहत पुलिस परेड ग्राउंड एवं आवासीय परिसर एवं जिले के सभी थानों के आसपास वृहद स्तर पर विभिन्न प्रकार के 1100 फलदार, छायादार, तथा औषधीय पौधों जैसे ऑम, अमरूद, ऑवला, पीपल, सहजन, बास इत्यादि का रोपण किया गया तथा उनकी सुरक्षा हेतु संकल्प लिया गया।एक पेड़ मॉ के नाम कार्यक्र म में विशेष न्यायाधीश रमा जयंत मित्तल, कुटुम्ब न्यायाधीश मुकेश कुमार, अति. जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश श्रीवास्तव, अति. जिला एवं सत्र न्यायधीश विकास सिंह चौहान, अति. जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र कुमार जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण डोडवे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनू जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी मिनी अग्रवाल, उप पुलिस अधीक्षक मुख्या. गायत्री तिवारी, रक्षित निरीक्षक सीधी विरेन्द्र कुमरे, थाना प्रभारी कोतवाली निरी-अभिषेक उपाध्याय, थाना प्रभारी महिला थाना निरी रीता त्रिपाठी, थाना प्रभारी अजाक निरी सुशीला वर्मा, कन्ट्रोल रूम प्रभारी निरी आर.एन. मिश्रा, थाना प्रभारी जमोड़ी उनि विशाल शर्मा, जिले के वरिष्ठ नागरिक, जिले के पत्रकार साथी एवं समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी, स्कूल के छात्र-छात्राएं व पुलिस परिवार के परिवार जन द्वारा पौधरोपण अभियान में उत्साह पूर्वक बढ़-चढ़कर भाग लिये और पौधरोपण कर वृक्ष के संरक्षण का संकल्प लिये।

घटिया स्तर के बनाये गये सब स्टेशन के चेंबर एवं पैनल भवन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के मशहूर अनशन मैन एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के म.प्र.प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने बिजली विभाग के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि जनपद पंचायत रायपुर कर्चु. के मनिकवार डी सी अंतर्गत ग्राम जरहा में एक वर्ष पूर्व करोड़ों रुपये की लागत से सब स्टेशन बनाया गया है,सब स्टेशन के निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग कर ठेकेदार ने सरकार को जमकर चूना लगाया है दरअसल ठेकेदार ने सब स्टेशन के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार मचाया है सब स्टेशन के चेंबर से लेकर पैनल भवन निर्माण में जिस तरह नंगा नाच नाचा है उसकी पोल खुलने लगी है जहां बारिश से सब स्टेशन के चेंबर के अंदर चारों तरफ खांईनुम गड्ढे हो गये हैं तो वहीं सब स्टेशन के पैनल भवन की छत बारिश समय में टपकाने लगी है साथ ही छत की सीलिंग भी क?ई जगह से गिर चुकी है गनीमत यह रही की सब स्टेशन में पदस्थ कर्मचारियों के ऊपर सीलिंग नहीं गिरी नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता है चूंकि सब स्टेशन में डियुटी कर रहे कर्मचारी उसी पैनल भवन में बैठकर सब स्टेशन का संचालन करते हैं ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार के खिलाफ जांच कराई जाकर ब्लैंक लिस्टेड किया जाय और सब स्टेशन में लगने वाली लागत राशि की वसूली की जाय यदि वसूली नहीं की गई तो सब स्टेशन में धरने पर बैठना पड़ेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

विचार

प्रधानमंत्री के खिलाफ बैल बुद्धि अभियान चला कर कांग्रेस ने बालक बुद्धि का परिचय दिया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर है। यह प्रतिद्वंद्विता चुनावों के दौरान तीखे हमलों में भी तब्दील हो जाती है। लेकिन जनता इसे सामान्य रूप में ही लेती है क्योंकि यह अपेक्षित ही है कि राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर हमले करेंगे ही लेकिन चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है जब राजनीतिक हमले शालीनता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पर जिस तरह के हमले किये जा रहे हैं वह राजनीति में शिष्टाचार खत्म होने का संकेत तो है ही साथ ही इससे यह भी प्रदर्शित हो रहा है कि कांग्रेस को मोदी को लगातार तीसरी बार मिला सरकार चलाने का जनादेश नहीं भाया है। कांग्रेस को समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी एक दल का नेता नहीं होता बल्कि वह समस्त भारतीयों का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति दुनिया में भारत का चेहरा होता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति से भले कितने भी वैचारिक और राजनीतिक मतभेद हों लेकिन उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही प्रधानमंत्री पर राजनीतिक हमले करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश के संवैधानिक पद का कोई अपमान नहीं हो जाये। लेकिन खेद की बात यह है कि देश पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली और देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के पद का लगातार अपमान करने में लगी हुई है। हम आपको याद दिला दें कि जब-जब गांधी परिवार के पास प्रधानमंत्री पद रहा तब-तब ही कांग्रेस ने इसका सम्मान किया। इतिहास उठा कर देखेंगे तो पाएंगे कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक...कांग्रेस को यह पचा ही नहीं कि कैसे कोई गैर-गांधी परिवार का व्यक्ति देश पर राज कर रहा है। पिछला उदाहरण डॉ. मनमोहन सिंह का है। जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उनके पास सारे अधिकार ही नहीं थे। मंत्री उनकी बात नहीं सुनते थे और सारे बड़े फैसले सोनिया गांधी करती थीं। इसके बाद जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तबसे कांग्रेस ने उनके खिलाफ निचले और निजी स्तर पर हमले करने का अभियान चलाया। मोदी पर कांग्रेस के हमलों का जवाब जनता चुनावों में देती रही लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सीटें क्या घटीं, कांग्रेस के हमले और निचले स्तर पर चले गये हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि करार देते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है जिसे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आगे बढ़ा रहे हैं। भले कांग्रेस ने यह अभियान प्रधानमंत्री की ओर से राहुल गांधी को बालक बुद्धि बताये जाने के जवाब में चलाया हो लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। संभव है कि कांग्रेस के बैल बुद्धि अभियान के जवाब में भाजपा भी कोई अभियान शुरू करे। लेकिन सवाल यह है कि इस सबसे क्या हासिल होगा? संभव है कि सोशल मीडिया पर ऐसे अभियानों को ज्यादा लाइक्स और रिपोस्ट मिल जायें लेकिन क्या ऐसे ही अभियानों से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है।

भारत-रूस मित्रता को जीवंतता देने का सार्थक प्रयास

ललित गर्ग

भारत-रूस की मैत्री को नये आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति पुतिन ने न केवल मैत्री के धागों एवं द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती दी है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को नये शिखर देने का प्रयास किया है। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के लिये एक नए सोच के साथ नये सफर का आगाज है। एक ऐसे समय में, जबकि यूक्रेन-रूस युद्ध को पश्चिमी देशों के विरोध के कारण रूस दुनिया में अलग-थलग है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पहले विदेश यात्रा के लिये रूस का चयन करके जता दिया है कि भारत-रूस की मैत्री अक्षुण्ण है और किसी भी तरह के दुनिया के दबाव में यह दोस्ती कमजोर नहीं पड़ने वाली है। भारत ने जहां मैत्री को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उपक्रम किये हैं, वहीं अपने मित्र देश को युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में अपना स्पष्ट रुख भी जताया है।

मोदी की इस यात्रा की एक बड़ी निष्पत्ति यह है कि रूस में अब दो नये वाणिज्यिक दूतावास खुलने जा रहे हैं, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से एवं ज्यादा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस रूस यात्रा को लेकर पश्चिमी देशों ने विरोध जताया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए रूस की मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। भारत अपने मैत्री-मूल्यों को किसी भी दबाव में कमतर नहीं होने देगा। भले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस यात्रा पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे शांति प्रयासों को झटका तक बता चुके हो या अमेरिका ने भी यात्रा को लेकर अपनी चिंता जता दी हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी युद्ध विरोधी सोच के चलते ही यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस नहीं गए थे। दोनों देशों के बीच होने वाली सालाना द्विपक्षीय शिखर बैठक भी 2022 के बाद से नहीं हो पाई थी। इससे रूस के कुछ हलकों में यह धारणा बनने लगी थी कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव में रूस से दूरी बनाए रखना चाहता है। दुनिया में बन रही इस नई धारणा को तोड़ना जरूरी था, इसी दृष्टि से इस यात्रा के पीछे जहां द्विपक्षीय रिश्तों को संदेहों और अविश्वासों से मुक्त करने का ध्येय था, वहीं अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह स्पष्ट संदेश भेजना था कि भारत को किसी तरह के दबाव के जरिए इस या उस पक्ष में झुकाना संभव नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया कि उनके रूस आने पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। दुनिया भर में इस यात्रा को गहरी उत्सुकता से देखा जा रहा है। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखें तो यह कोई अचरज वाली बात भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का जोर इस बात पर रहा है कि भारत रूस से अपनी करीबी खत्म करे। भारत अब एक स्वतंत्र ताकत है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, बड़े शक्तिशाली देशों के लिये भी भारत एक बाजार है। इसलिये भारत किसी भी दबाव में न आते हुए शुरू से ही यह स्पष्ट कर रखा है कि वह अपने राष्ट्रहित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा। रूस समर्थकों ने भले ही यह दर्शाना चाहा हो कि मोदी की यात्रा से भारत ने पश्चिम को चुनौती दी है और इससे पश्चिमी देश 'ईर्ष्या से जल रहे हैं', परंतु असल में भारत ऐसा कोई मंतव्य नहीं रखता है। यह यात्रा अनेक कारणों एवं दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रही, यात्रा के दौरान दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने के समझौते तो हुए ही, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र राष्ट्र को मैत्रीपूर्ण सलाह देते हुए पूरी बेबाकी से कहा, 'युद्ध के मैदान से कोई हल नहीं निकलता।' यह प्रधानमंत्री मोदी का वैसा ही बयान है जैसा दो साल पहले समरकंद में पुतिन से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया था कि 'यह युद्ध का दौर नहीं है'। असल में भारत हमेशा से शांति के उजालों एवं युद्ध के अंधेरों से मुक्ति का ही समर्थक रहा है। भारत की स्पष्ट मान्यता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत ने बम-बंदूक के बजाय शांति-वार्ता के जरिये समाधान की बात दोहराई। मोदी ने साहस एवं निर्भयता से पुतिन को दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच यह भी कह दिया कि युद्ध या संघर्ष अथवा आतंकी हमलों में जब मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है। देखना यह है कि यूक्रेन युद्ध पर भारतीय प्रधानमंत्री की फिर से खरी बात पर रूसी राष्ट्रपति कितना ध्यान देते हैं, लेकिन भारत को रूस के साथ अपनी मित्रता जारी रखते हुए यह स्पष्ट करते रहना होगा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त होते हुए देखना चाहता है। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के भी हित में है। इसी के साथ भारत ने अपने मित्र देश को अपनी तकलीफ को साझा करते हुए यह एहसास दिलाने की भी कोशिश की गई कि चीन के साथ उसकी नजदीकी परोक्ष रूप से पाकिस्तान को उत्साहित करती है, जो भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों को खाद-पानी मुहैया कराने का काम करता है। रूस भारत के सहयोग के लिये तत्पर रहता है, इसबार भी यह खबर भी सुकून देने वाली है कि रूस ने भारत के आग्रह पर न केवल रूसी सेना के सपोर्ट स्टाफ के रूप में भारतीयों की नियुक्ति रोकना स्वीकार कर लिया है बल्कि नियुक्त किए जा चुके युवाओं को स्वदेश भेजने पर भी मान गया है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सफल कूटनीति के एक उत्तम उदाहरण के रूप में याद रखी जाएगी। भारतीय हितों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व मानवता की बात करना इसी रणनीति का हिस्सा था। अन्य पहलू है, इस द्विपक्षीय रिश्ते में कौन-कौन से नए क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं, ताकि यह संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। विज्ञान-प्रौद्योगिकी और 'पीपुल-टु-पीपुल कॉन्टैक्ट' यानी आम लोगों के स्तर पर आपसी संबंध को आगे बढ़ाने पर रजामंदी को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आने वाली दिक्कतों को दूर करना। भुगतान की टिकाऊ व्यवस्था पर जोर इसकी एक बानगी है। अच्छी बात यह भी रही कि ईंधन के मामले में भारत को स्थिरता प्रदान करने में रूसी योगदान की प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर सराहना की, जो उचित भी था, क्योंकि अब हम खाड़ी देशों के बजाय सबसे अधिक तेल रूस से ही आयात करने लगे हैं। भारत-रूस की मैत्री का व्यापक महत्व है। यह पुराना मित्र देश का भारत की ताकत रहा है, मार्गदर्शक रहा है, हर सुख-दुःख का साथी रहा है। नेहरु युग से ही भारत-रूस के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों की संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य के बीच भी गहरा आत्मीय लगाव रहा है। भारतीय फिल्में रूस में बड़े चाव से देखी जाती रही है। कश्मीर के मसले पर भारत जब-जब अलग-थलग पड़ता रहा, तब तब रूस ने भारत का साथ दिया। 1955 में रूस के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव ने कश्मीर पर भारतीय संप्रभुता के लिए समर्थन की घोषणा करते हुए कहा था, 'हम इतने करीब हैं कि अगर आप कभी हमें पहाड़ की चोटियों से बुलाएंगे तो हम आपके पक्ष में खड़े होंगे।' आश्वासन सिर्फ मुंहजबानी नहीं था बल्कि सोवियत संघ ने 1957, 1962 और 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों को वीटो कर दिया था, जिसमें कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की बात कही गई थी। भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान भी जब पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका भारत पर लगभग आक्रमण करने ही वाला था, तब रूस द्वारा भारत के पक्ष में भेजी गई सैन्य सहायता ने ही अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर किया था। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी रूस का अनूठा योगदान रहा है। रूस ने ही भारत को सैन्य हथियारों व अन्य साजोसामान की आपूर्ति करके अपने दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ बनाया है। ऐसे भरोसेमंद देश के साथ जब बीच के दौर में आर्थिक कारणों व वैश्विक दबावों के चलते दूरी आने लगी थी तो दोनों ही देशों की जनता ने मांग उठायी कि ऐसे विश्वसनीय सहयोगी को खोना उचित नहीं होगा। मोदी की यात्रा से भारत-रूस संबंधों एवं मित्रता की नई इबारत लिखी गयी है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम सुखद होने वाले हैं।

धर्मोन्मूलन पर न्यायालय की चिन्ता और सरकार की उदासीनता

मनोज ज्वाला

खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अनुसूचित जातीय-जनजातीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को क्रिश्चियनिटी अथवा इस्लाम में तब्दील किए जाने के व्यापक रिलीजियस-मजहबी अभियान चिंता जताते हुए कहा है इसे यदि रोका नहीं गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी शीघ्र ही अल्पसंख्यक हो जाएगी या मुसलमान और तब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड जाएगी; अतएव सरकार कठोर कानून बना कर इस अभियान पर तत्काल रोक लगावे। ऐसी ही चिंता पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय भी जता चुका है। हालांकि दोनों ही न्यायालयों ने इसे %ईसाईकरण% अथवा 'इस्लामीकरण' की संज्ञा देते हुए ऐसा कहा है, किन्तु मेरा मानना है कि यह धर्मांतरण कतई नहीं है, अपितु यह तो 'धर्मोन्मूलन' है; क्योंकि बहुसंख्यक समाज धर्मधारी है और क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, तो इस्लाम भी एक मजहब है। इन दोनों में से 'धर्म' कोई नहीं है, तो जाहिर है कि धर्मधारी लोगों को रिलीजन या मजहब में तब्दील कर देना उनके धर्म का उन्मूलन ही है 'अंतरण' तो कतई नहीं; यह धर्मांतरण तो तब कहलाता, जब एक धर्म से दूसरे धर्म में अन्तरण होता, अर्थात, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी कोई धर्म होता। बहरहाल, धर्मोन्मूलन को धर्मान्तरण ही मानते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने सरकार को जो निर्देश दिया है सो त्वरित क्रियान्वयन के योग्य है। धार्मिक स्वतंत्रता की आड में धर्मधारी प्रजा (बहुसंख्यक हिन्दू समाज) के ईसाईकरण अथवा इस्लामीकरण का छद्म अभियान चला रहे रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं को परोक्षत: करारा जवाब देते हुए उच्च न्यायालय ने

यह भी कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी धार्मिक व्यक्ति को धर्म से विमुख कर उसे रिलीजन या मजहब में तब्दील कर दिया जाए। बकौल न्यायालय, लोभ लालच प्रलोभन दे कर या भयभीत कर भोले-भाले (धार्मिक) लोगों का ईसाईकरण अथवा इस्लामीकरण किया जाना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। सर्वोच्च न्यायालय का तो यह भी मानना है कि इस प्रकार के अभियान से भारत राष्ट्र की एकता-अखण्डता व राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है; अतएव इसे रोका जाना अनिवार्य है। जाहिर है सर्वोच्च न्यायालय की यह चिन्ता व मान्यता भारत के 'राष्ट्रीय युवा'- स्वामी विवेकानन्द और महान स्वतंत्रता सेनानी महर्षि अरविन्द के चिन्तन-उद्बोधन पर आधारित है । मालूम हो कि स्वामी विवेकानन्द ने कह रखा है कि धर्मांतरण एक प्रकार से राष्ट्रान्तरण है। धर्म से विमुख हुआ व्यक्ति जब 'रिलीजन' व 'मजहब' को अपना लेता है, तब वह प्रकारान्तर से भारत के विरुद्ध हो जाता है; क्योंकि धर्म तो भारत की आत्मा है, जबकि 'रिलीजन' व 'मजहब' अभारतीय अवधारणा हैं। इसी तरह से महर्षि अरविन्द का कथन है कि धर्म (सनातन) ही भारत की राष्ट्रीयता है और धर्मांतरण से भारतीय राष्ट्रीयता क क्षरण अवश्यम्भावी है। भारत के इतिहास और भूगोल में यह तथ्य सत्य सिद्ध हो चुका है। भारत-विभाजन अर्थात पाकिस्तान-सृजन और खण्डित भारत के भीतर यत्र-तत्र रिलीजियस-मजहबी जनसंख्या के बढते आकार से उत्पन्न विभाजनकारी पृथकतावादी आन्दोलन इसके प्रमाण हैं। सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त चिन्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। इसी कारण से महात्मा गांधी भी धर्मांतरण का मुखर विरोध करते रहे थे एवं चर्च-मिशनरियों की गतिविधियों पर लगातार सवाल उठाते रहते थे और यहां तक कह चुके थे कि स्वतंत्र भारत में धर्मांतरणकारी संस्थाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 'क्रिश्चियन मिशन्स- देयर प्लेस इन इण्डिया' नामक पुस्तक के 'टॉक विथ मिशनरिज' अध्याय में महात्मा गांधी के हवाले से कहा गया है कि भारत में आम तौर पर ईसाइयत का अर्थ भारतीयों को राष्ट्रीयता से रहित बनाना तथा उनका युरोपीकरण करना है। आगे वे कहते हैं- भारत में ईसाइयत अराष्ट्रीयता एवं युरोपीकरण का पर्याय हो चुकी है। चर्च-मिशनरियां धर्मांतरण का जो काम करती रही हैं, उन कामों के लिए स्वतंत्र भारत में उन्हें कोई भी स्थान एवं अवसर नहीं दिया जाएगा; क्योंकि वे समस्त भरतवर्ष को नुकसान पहुंचा रही हैं। भारत में ऐसी किसी चीज का होना एक त्रासदी है। सन 1935 में चर्च-मिशन की एक प्रतिनिधि से हुई भेंटवार्ता में महात्मा साफ कहा था- अगर सत्ता मेरे हाथ में हो और मैं कानून बना सकूं तो मैं धर्मांतरण का यह सारा धंधा ही बन्द करा दूंगा।(सम्पूर्ण गांधी वांग्मय- खण्ड 61) बावजूद इसके आज देश भर में ऐसी रिलीजियस-मजहबी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है, जो शिक्षा-स्वास्थ्य-सेवा के विविध प्रकल्पों और सामाजिक न्याय व समता-स्वतंत्रता के विविध आकर्षक सब्जबागों एवं विकास-परियोजनाओं की ओट में देसी-विदेशी धन के सहारे छलपूर्वक धर्मांतरण का धंधा संचालित कर रही हैं। इन संस्थाओं की कारगुजारियों के कारण यहां कभी 'असहिष्णुता' का ग्राफ ऊपर की ओर उठ जाता है, तो कभी 'अल्पसंख्यकों की सुरक्षा' का ग्राफ नीचे की ओर गिरा हुआ बताया जाता है। ये संस्थायें भिन्न-भिन्न प्रकृति और प्रवृति की हैं। कुछ शैक्षणिक-अकादमिक हैं, जो शिक्षण-अध्ययन के नाम पर भारत के विभिन्न मुद्दों पर तरह-तरह का शोध-अनुसंधान करती रहती हैं; तो कुछ संस्थायें ऐसी हैं, जो इन कार्यों के लिए अनेकानेक संस्थायें खडी कर उन्हें साध्य व साधन मुहैय्या करती-कराती हुई विश्व-स्तर पर उनकी नेटवर्किंग भी करती हैं। %फ्रीडम हाउस% संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐसी ही संस्था है, जो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर उन्हें भडकाने के लिए विभिन्न भारतीय-अभारतीय संस्थानों का वित्त-पोषण और नीति-निर्धारण करती है। किन्तु वास्तव में धर्मोन्मूलन (अर्थात ईसाईकरण या इस्लामीकरण) और भारत-विभाजन ही इसका गुप्त एजेण्डा है, जिसके लिए यह संस्था भारत में कथित अल्पसंख्यकों के उत्पीडन की इक्की-दुक्की घटनाओं को भी बढा-चढा कर दुनिया भर में प्रचारित करती है। इसी तरह से 'दलित फ्रीडम नेटवर्क' (डीएफएन) नामक एक अमेरिकी संस्था का नियमित पाक्षिक प्रकाशन भी है- 'दलित वायस' जो भारत में पाकिस्तान की तर्ज पर एक पृथक 'दलितस्तान' राज्य की भी वकालत करता रहता है। इन दोनों संस्थाओं को अमेरिकी सरकार का ऐसा वरदहस्त प्राप्त है कि वे अमेरिका-स्थित विभिन्न सरकारी आयोगों के समक्ष भारत से रिलीजियस-मजहबी कार्यकर्ताओं को ले जा- ले जाकर भारत-सरकार के विरूद्ध गवाहियां दिलाता है।

महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, इस साल 465 नक्सली कर चुके हैं समर्पण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)।छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एक महिला नक्सली समेत चार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि चार नक्सलियों दिरदो हिड़मा (39), महिला नक्सली सोड़ी सोमे (30), पोड़ियाम हुंगा (25) और मुचाकी देवा (55) ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि नक्सली दिरदो हिड़मा पर एक लाख रुपये का इनाम है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की 'नियद नेल्ला नार' (आपका अच्छा गांव) योजना से प्रभावित होकर तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव से तंग आकर आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ पुलिस दल पर हमला, मार्गों को काटना और नक्सली पर्चे लगाने जैसे कार्यों में शामिल होने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधायें प्रदान की जाएगी।

इस साल 465 नक्सली कर चुके हैं सरेंडर: इस वर्ष अब तक नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने बस्तर क्षेत्र में 137 नक्सलियों को मार गिराया है तथा इस दौरान 498 चरमपंथी गिरफ्तार किए गए हैं और 465 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य से नक्सलवाद खत्म करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी वजह से लगातार सुरक्षाबल कार्रवाई कर रहे हैं और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कई तरह की सुविधाएं भी दा जी रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हों। आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।

आठ लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली ढेर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में आठ लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली को मार गिराया था। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनागुंडा गांव के करीब जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में महिला नक्सली रीता मड़ियाम (30) को मार गिराया है।

छोटेबेठिया थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संयुक्त दल को गश्त के लिए रवाना किया गया था तथा दल जब बीनागुंडा गांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने जब घटनास्थल की तलाशी ली तब वहां एक महिला नक्सली का शव, एक 303 की राइफल, एक 315 बोर की राइफल और भारी मात्रा में हथियार तथा नक्सली सामान बरामद किया।

उचित मूल्य दुकान ग्राम रतनपुर के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (एजेंसी)। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खड़गवां द्वारा सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान रतनपुर (आई.डी.क्र. 532004046) का निरीक्षण जिला खाद्य अधिकारी श्री संजय ठाकुर, खाद्य निरीक्षक खड़गवां श्री दीपक कुमार प्रधान एवं खाद्य निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ श्री सदानंद पैकरा द्वारा किया गया। कार्यालय को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार जांच में गंभीर अनियमितता पाई गयी। संचालनकर्ता एजेंसी ग्राम पंचायत रतनपुर को आबंटित शा.उ.मू.दुकान रतनपुर आई.डी. क्र.532004046 को निरस्त कर नजदीकी शा. उ. मू. दुकान कोड़ागी आईडी.क्र. 532004072 (रोशनी महिला स्व. सहायता समूह कोड़ागी) में संलग्न किया गया है। इस हेतु आदिम जाति सहकारी समिति, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, वन सुरक्षा समिति एवं अन्य समितियों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही किया जाना है। अतः उपरोक्त संबंधितों से 09 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2004 कार्यालयीन समय तक पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य सम्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

होटल में महिला और रेलवे ट्रैक पर प्रेमी का मिला शव

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)।छत्तीसगढ़ में 26 साल की एक महिला की उसके 30 वर्षीय प्रेमी ने हत्या कर दी। हालांकि हत्या क्यों की गई है, इसका अभी भी खुलासा नहीं हो सका है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के मामले का खुलासा हो सकेगा। दरअसल, महिला का शव होटल के एक कमरे में मिला है, जबकि उसके प्रेमी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या करने के बाद प्रेमी ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार महिला वाणी गोयल का शव होटल के कमरे में मिला, जबकि उसके प्रेमी विशाल गर्ग का शव दिन में उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियों पर पड़ा मिला। एक अधिकारी ने बताया कि सरस्वती थाना क्षेत्र के निवासी विशाल गोयल के परिवार के सदस्यों ने शनिवार को उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। उन्होंने कहा, "वाणी के मोबाइल की लोकेशन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर में मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। पुलिसकर्मियों को उसका मोबाइल फोन तो मिल गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।"

अधिकारी ने बताया कि इस बीच, विशाल गर्ग का शव खमतराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियों से मिला। विशाल सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर का निवासी था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि वीणा रायपुर के जेल रोड इलाके में स्थित 'होटल बेबीलोन इन' के एक कमरे में फर्श पर मृत पड़ी है।

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि महिला की पिटाई की गई और गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम से पता चलेगा। दस्तावेजों और सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि दोनों शनिवार दोपहर करीब 1.30 बजे होटल में आए थे। उन्होंने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गर्ग ने आत्महत्या करने से पहले महिला की कथित तौर पर हत्या की। हालांकि, मामले की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़ सरकार 47 हजार से ज्यादा परिवारों को देगी मकान

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)।छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जनता को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बेघर के रूप में पहचाने गए 47 हजार 90 परिवारों को मकान दिया जाएगा। मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है।

कौन होगा पात्र?

दरअसल, छत्तीसगढ़ में पिछले साल कांग्रेस शासन के दौरान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। इनमें से 47 हजार 90 परिवारों को बेघर के रूप में पहचाना गया था। अब इन जरूरतमंद आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास देने का फैसला किया गया है।

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन हैं, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीकरण की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर ने शिविर में ग्रामीणों से रूबरू होकर जानी लोगों की समस्याएं

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (एजेंसी)। ग्राम भौता में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर के पहले दिन भौता स्कूल में आयोजित किया गया। शिविर स्थल पर कृषि विभाग के द्वारा संचालित कृषक हितैषी योजनाओं का बताया गया लाभ व राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत कृषकों को खाद-बीजों का वितरण किया गया, स्वास्थ्य विभाग द्वारा हितग्राहियों के मेडिकल टेस्ट कर उन्हें बुखार, उल्टी- दस्त, पेट-दर्द, हीमोग्लोबिन, शुगर जैसी दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के कुल 80 नए फॉम भरे गए व 34 आयुष्मान कार्ड धारकों को तुरन्त आयुष्मान कार्ड मुहईया करवाया गया, शिविर में ग्रामीणों की सिकलसेल 25 जांच किये व 15 सिकल सेल कार्डों का वितरण त्वरित किया गया। मतस्य पालन विभाग की ओर से 02 हितग्राहियों को जाल का वितरण किया गया, वन विभाग द्वारा शिविर में आये ग्रामीणों को "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत फलदार पौधों का वितरण किया, ग्राम छिपछिपी के शासकीय हाई स्कूल की कक्षा नवमी की छात्राओं को सरस्वती सायकल वितरण के अंतर्गत कुल 16 सायकलों का वितरण किया गया, दिव्याग योजना के अंतर्गत समाज कल्याण द्वारा दिव्यांगो को मोटराईज्ड सायकल, छड़ी व व्हील चेयरों का वितरण भी किया गया।

आवेदन लेकर पहुंचे एक दिव्यांग के आवेदन पर कलेक्टर श्री डी.राहुल वेंकट ने शिविर स्थल पर निराकरण किया, उन्हें तत्काल ट्राइसिकल देने के निर्देश दिये। इसके पूर्व विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में योजनाओं का लाभ प्राप्त करें, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सम्बंधित विभाग में संपर्क करने का सुझाव भी दिये गये। कलेक्टर ने आम नागरिकों से रूबरू होकर समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। कुछ के लिए समय-सीमा निश्चित कर समाधान करने, कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए।

विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री डी.राहुल वेंकट ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि शासन-प्रशासन के सभी विभागों को एक जगह उपस्थित होकर आम लोगों की समस्या, जरूरत, मांग को यथा समय समाधान करना है ताकि जरूरतमंद व पात्र हितग्राहियों व जनहित के मुद्दे का निराकरण हो सके है।

मिड-डे मील में बच्चों की थाली से दाल और सब्जी गायब

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर इलाके के एक स्कूल में बच्चों की थाली से दाल और सब्जी ही गायब दिखी है। बच्चों को चावल में सिर्फ हल्दी डालकर खिलाया जा रहा है। बच्चों ने कहा कि एक सप्ताह से उन्हें मिड-डे मील में सब्जी खाने को नहीं मिली है। मिड-डे मील में गड़बड़ी का मामला वाड्रफनगर के बिजाकुर के प्राथमिक शाला पटेल पारा का है।

छत्तीसगढ़ के बिजाकुर के प्राथमिक स्कूल में बच्चों को मिड-डे मील में सादा चावल दिया गया। सब्जी और दाल की तरह दिखने के लिए चावल में ही थोड़ी हल्दी डाल दी गई। ऐसा इसिलए किया गया ताकि बच्चों को लगे ये कोई खिचड़ी या दाल-चावल है।

बलरामपुर के पटेल पारा के बिजाकुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में 43 बच्चों को मिड-डे मील दिया जाता है। स्कूल के टीचरों ने माना कि वे करीब एक हफ्ते से मीड-डे मील में कोई सब्जी नहीं परोस रहे हैं। खाने में चावल और दाल या सिर्फ हल्दी चावल ही शामिल है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं ने सब्जियां उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिए मिड-डे मील के खाने में बच्चों को हरी सब्जियां नहीं दे पा रहे हैं।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने मिड-डे मील के लिए एक निर्धारित मेनू बनाया है। इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन दिए जाने का वादा किया गया है। शिक्षा विभाग के इस मेनू से अलग बच्चों को खाने में सिर्फ चावल में हल्दी मिलाकर खिलाई जा रही है। इस लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र नाथ मिश्रा ने तत्काल जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

ग्राम पंचायत भौंता में किया गया जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देशानुसार आज जिला मनेंद्रगढ़.चिरमिरी.भरतपुर के विकासखंड मनेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत भौता में 5 ग्राम पंचायतों नारायणपुर छिपछिपीए बंजीए बुंदेली तथा पाराडोल को सम्मिलित कर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजिन किया गया। शिविर का शुभारंभ भौता की सरपंच श्रीमती मुन्नीबाईए एसडीएम लिंग राज सिदार तथा जनपद सीईओ कुमारी वैशाली के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्जलित कर किया गया। जिला स्तरीय समस्या निवारण शिविर में जिला सदस्य कोरिया श्रीमती उषा सिंह करियाम, छिपछिपी जनपद सदस्य निशा सिंह, कलेक्टर डी.राहुल वेंकट, अपर कलेक्टर श्री अनिल सिदार, परियोजना निदेशक नितेश उपध्याय, छिपछिपी सरपंच राम सिंह, नारायणपुर सरपंच मुन्ना लाल, बंजी सरपंच श्रीमती सुमित्रा, बुंदेली सरपंच आनन्द भगत तथा पाराडोल सरपंच अभिराज सिंह सहित सर्व पंचायत सचिव, कोटवार सहित पांचों ग्रामों ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आम जनों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती माता रीना पति उदयभान, सीमा पति सुखलाल, तारा पति विनोद, मानमती पति राम प्रसाद, शशिकला पति शिवकुमार तथा दुर्गावती पति परमेश्वर की गोद भराई कर अच्छी पौष्टिक आहार लेने के लिए कहा गया इसी के साथ ही समस्त 6 माह के बच्चे अनुसुईया पिता शिवनारायण, मंजू पिता महिप सिंह, मनीष पिता चंद्रभान, अमित पिता शंकर सिंह तथा अंजू पिता सोमार साय का जनप्रतिनिधियों द्वारा अन्नप्राशन का रस्म कराया गया। कृषि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नारायणपुर के 8 बैगा जनजाति के हितग्राहियों जयराम आ. मंगला, मोहन आ. इकालू, शिवलाल आ. बुद्धू, बीरसाय आ. राय सिंह, ज्ञान सिंह आ. मैकू, बिरझू आ. मंगला, वीर सिंह आ. सुखीराम तथा रंगलाल आ. बुद्धू को रागी की बीज वितरण किया गया। इसी प्रकार कृषि विभाग से नारायणपुर के अनुसूचित जनजाति के हितग्राही देवनारायण पिता बहादुर, सुकल साय पिता टेहे तथा रामू पिता अधीन सिंह को सॉयल सैम्पल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। जनसमस्या निवारण शिविर में राजस्व विभाग के 23, जनपद पंचायत के 29, वन विभाग के 01, शिक्षा विभाग के 07,छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल के 13, जल संसाधन के 04, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के 03, आदिवासी विकास के 01, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 12,प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 02, अग्रणी बैंक प्रबंधक के 01, पुलिस विभाग के 01, जिला स्वच्छ भारत मिशन के 01, ग्राम पंचायत छिपछिपी के 01, ग्राम पंचायत नारायणपुर के 02, ग्राम पंचायत भौंता 06, महिला एवं बाल विकास विभाग के 01, कृषि विभाग के 01, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 01, समाज कल्याण विभाग के 01 तथा खाद्य विभाग के 01 मांग एवं समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुये। सबको मिलाकर कुल 112 आवेदन प्राप्त हुये इनमें 18 का निराकरण शिविर स्थल पर ही किया गया तथा शेष 94 आवदेन लंबित है। लंबित आवेदनों को विभागवार समीक्षा करते हुये प्राक्कलन तैयार कर आवेदनों संबंधित विभागों द्वारा यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने शिविर स्थल पर हितग्राहियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिला मुख्यालय में बैठकर बहुत बार हम बहुत लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं कर पाते या फिर समय के अभाव के चलते हम लोग आप तक पहुंच नहीं पाते तो उसी के सिलसिले में यहां पर शिविर का आयोजन किया गया। समस्याओं का निराकरण करने के लिए यह प्रयास हमाराए शासन और प्रशासन तथा आप सबका हैए और इसके लिए शिविर होते रहते होने चाहिए। हमारा ऐसा है कि जिला स्तर पर दो विधानसभा क्षेत्र हैं एक भरतपुर सोनहत और दूसरा मनेंद्रगढ़। तो हर महीने एक.एक शिविर आयोजन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में होता रहे। जिससे क्षेत्र में बहुत सारी छोटी.छोटी त्रुटियां को हम धीरे.धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे और जितनी भी जो छोटी.मोटी समस्याओं का हुआ है और बहुत कुछ समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है तो हम आगे जो भी समय सीमा की बैठक में आएगा तो उल्लेख करेंगे कि कितने का निराकरण हुआ और उसके लिए अलग से समय भी दिया जाएगा ताकि हम लोगों बता सके कि उनके बीच जाकर कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है और कितने का निराकरण करना बाकी है। ताकि उसका परिणाम फील्ड पर पहुंच सके। शिविर में जितने प्रकरणों का निराकरण हो गया है उतना तो ठीक है पर जो भी नहीं हुआ है वह मेरी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी। उसको हम धीरे.धीरे निराकरण करने का प्रयास करेंगे आगे कहीं पर भी शिविर का आयोजन हो तो वहां पर भी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जनता शिविर में योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास करें।

लकड़ी का एक टुकड़ा बना 5 लोगों की मौत का कारण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (एजेंसी)। छत्तसीगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां लकड़ी का एक टुकड़ा 5 लोगों की मौत का कारण बन गया है। घटना होने के बाद गांव के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी का टुकड़ा पांच लोगों की मौत का कारण कैसे बन सकता है। यह समझाने के लिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। हैरान कर देने वाला यह मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले का है। आज यानी 5 जुलाई को एक कुएं में 5 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक रामचंद्र जायसवाल नाम का एक शख्स कुएं में गिरे लकड़ी के टुकड़े को निकालने के लिए उतरा। मगर वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला। इसके बाद उसके परिजनों ने पड़ोस के पटेल और चंद्रा परिवार से मदद मांगी। कुएं में गए शख्स को बचाने के लिए रमेश पटेल, जितेंद्र पटेल, राजेंद्र पटेल और टिकेश्वर चंद्रा नाम के चार लोग कुएं में उतर गए मगर वो भी बाहर नहीं निकल पाएं और उनकी मौत हो गई।

9 महीने बाद बर्फ के पहाड़ से निकाले गए 3 सैनिकों के शव

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने सैनिक द्वारा 3 शवों को निकालने के अभियान की प्रशंसा की। अधिकारी ने बताया है कि अक्टूबर 2023 में लद्दाख में 18,300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उनके पर्वतारोहण अभियान दल के हिमस्खलन की चपेट में आने से मारे गए तीन सैनिकों के शवों को निकालने में 9 महीने से अधिक समय क्यों लगा? ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही (सेवानिवृत्त) ने एक्स पर एक पोस्ट में शवों को निकालने के लिए गुलमर्ग स्थित हाई-अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल (एचएडब्ल्यूएस) के सैनिकों को धन्यवाद दिया और बधाई दी। हवलदार रोहित कुमार, हवलदार ठाकुर बहादुर आले और नायक गौतम राजबंशी के शव एक दरार में फंस गए थे और पिछले 9 महीनों से बर्फ की मोटी परतों और बड़ी मात्रा में बर्फ के नीचे दबे हुए थे।

जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 14 जुलाई से खुलने की संभावना

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गुरुवार को कहा कि 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 14 जुलाई को खुलने की संभावना है। हरिचंदन ने संवाददाताओं से कहा कि मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर के रत्न भंडार को 14 जुलाई को खोलने के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंदिर प्रबंध समिति ने बुधवार को पुरी में बैठक की और उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाए गए कुछ एसओपी में मामूली बदलाव करने के बाद न्यायमूर्ति रथ समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रबंध समिति ने राज्य सरकार को प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी भेजकर 14 जुलाई को रत्न भंडार खोलने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। कानून मंत्री ने कहा कि मंदिर प्रबंध समिति के प्रस्ताव की सरकार द्वारा गहन जांच की जाएगी और रत्न भंडार को संभवत: 14 जुलाई को खोला जाएगा जैसा कि उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिया था और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति ने मंजूरी दी थी।

हवाई अड्डे पर उतरते समय विमान में लगी आग, फ्लाइट में 275 यात्री और क्रू के 21 सदस्य सवार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सउदी एयरलाइंस के एक विमान में गुरुवार को आग लग गई जिसके बाद विमान की पेशावर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई।यह विमान रियाद से आ रहा था हालांकि इसमें मौजूद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान में इसकी जानकारी साझा की है। सऊदी एयरलाइंस 792 विमान बुधवार को जब पेशावर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो उसमें से धुआं निकलता दिखाई दिया जिसके फौरन बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को इसकी जानकारी दी और फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को भी इसकी जानकारी दी गई जिससे कि आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक, यह विमान सऊदी अरब के रियाद से पेशवार आया था।

नेपाल में सियासी भूचाल

विरोधियों के दांव से चित हो गए पीएम पुष्प कमल दाहाल

काठमांडू (एजेंसी)। सियासी संकटों के बीच घिरे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' शुक्रवार को संसद में विश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को उनकी मुश्किलों को और बढ़ाते हुए नेपाली कांग्रेस और 'सीपीएन-यूएमएल' ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनके खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी केपी शर्मा ओली नीत 'सीपीएन-यूएमएल' ने पिछले सप्ताह %प्रचंड% के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी संबंधी समझौता किया था। माना जा रहा है कि दाहाल विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे।

नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस के पास फिलहाल 89 सीट हैं, जबकि सीपीएन-यूएमएल के पास 78 सीट हैं। निचले सदन में 138 सीटों के बहुमत के मुकाबले दोनों दलों के पास कुल 167 सदस्य हैं। प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माउइस्ट सेंटर) के पास 32 सीट हैं। प्रचंड को अपनी सरकार बचाने के लिए सदन में 138 सदस्यों का समर्थन चाहिए लेकिन उन्हें 63 सदस्यों का समर्थन मिलने की संभावना है और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि उनकी सरकार शुक्रवार को विश्वासमत हार जाएगी।

'माइ रिपब्लिका' अखबार की खबर के मुताबिक नेपाली कांग्रेस ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित होने और %प्रचंड% के विश्वासमत प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार, 'सीपीएन-यूएमएल' ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने को कहा है। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल का यह संयुक्त प्रयास प्रचंड नीत सरकार को अपदस्थ करने और संघीय और प्रांतों के स्तर पर अपनी सरकार बनाने के लिए है।

'सीपीएन-यूएमएल' अध्यक्ष ओली ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा से बुधवार को मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की बैठक का उद्देश्य नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी-एकीकृत माओवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) गठबंधन के बाद आगे की रणनीति और नई गठबंधन सरकार बनाने को लेकर चर्चा करना था। काठमांडू के बाहरी इलाके बूढ़ानीलकंठ में देउबा के आवास पर हुई दो घंटे की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने ओली के नेतृत्व वाले नए गठबंधन के पक्ष में हस्ताक्षर लेने और इसे राष्ट्रपति को सौंपने जैसे मामलों पर चर्चा की। सीपीएन-यूएमएल के सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने नई सरकार बनाने और ओली के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहमति की सरकार बनाने के लिए छोटे दलों को आमंत्रित करने पर चर्चा की। दोनों दलों ने संसद के शेष बचे तीन साल के कार्यकाल के लिए बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करने संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आलिया नीलम ने लाहौर उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

लाहौर (एजेंसी)। कंगाली, गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद और महंगाई जैसे मुद्दों में घिरा रहने वाला पाकिस्तान अब एक महिला की वजह से चर्चा में आ गया है। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने बृहस्पतिवार को लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश पद की शपथ ली है। खास बात यह है कि नीलम पाकिस्तान की पहली महिला हैं जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के पद पर आसीन हुई हैं। पंजाब के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। पंजाब सूबे की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं।

वायरल हुई तस्वीर: न्यायमूर्ति नीलम (57) लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर थीं लेकिन पाकिस्तान के प्रधान न्यायधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाले न्यायिक आयोग ने उन्हें इस पद के लिए नामित करने का फैसला किया। नीलम को मुख्य न्यायधीश बनाने की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी सत्तारूढ़ शरीफ परिवार के सदस्यों के साथ खींची गई तस्वीर वायरल होने लगी। इसके जरि उनके विरोधी यह संकेत करना चाहते थे कि वह सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग (नवाज) से जुड़ी हुई हैं।

कैसा रहा करियर: न्यायमूर्ति नीलम का जन्म 12 नवंबर 1966 में हुआ और उन्होंने 1995 में पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की है। 1996 में वकील के तौर पर उन्होंने अपना पंजीकरण कराया। न्यायमूर्ति नीलम ने 2008 में अधिवक्ता के तौर पर उच्चतम न्यायालय में पंजीकरण कराया। वह 2013 में लाहौर उच्च न्यायालय की अस्थायी न्यायधीश बनीं और 16 मार्च 2015 को उन्हें पदोन्नति देकर स्थायी न्यायधीश बना दिया गया।

नीट पर सुनवाई अब 18 जुलाई को

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी । कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। सुनवाई के लिए 11 जुलाई को कोर्ट में नीट का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। केस 33 की सुनवाई के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कल सबसे पहले नीट पर सुनवाई होगी। इसके बाद इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को केस की सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की। फिलहाल, कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है । सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की बेंच के सामने नीट मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट दी गई थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे।

सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस संजय कुमार हटे

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने गुरुवार (11 जुलाई) को आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। अब 15 जुलाई को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस संजय कुमार इसका हिस्सा नहीं होंगे। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

बोली- केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना

नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब नीति केस में श्वष्ठ ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सातवीं सप्लिमेंट्री चार्जशीट पेश की। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया। चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल ने 2022 में हुए गोवा चुनाव में आप के चुनाव अभियान में यह पैसा खर्च किया। दावा किया गया है कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रेक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से

45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। ईडी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि क्क के पूर्व मीडिया प्रभारी और इस केस के सह-आरोपी विजय नायर ने उनके नहीं, बल्कि मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि सीएम ने कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा के राज्य प्रभारी थे और फंड का प्रबंधन करते थे और फंड से संबंधित निर्णयों में उनकी खुद कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता से रिश्वत नहीं मिली थी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल को 4 हफ्ते का समय दिया है।

लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनीं आलिया नीलम

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में गुरुवार को आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। पंजाब प्रांत के न्यायिक इतिहास में ये पहली बार है जब कोई महिला शीर्ष पद पर बैठी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बुधवार को उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम को पंजाब गर्वनर सरदार सलीम हैदर खान ने शपथ दिलाई। इस दौरान पंजाब की पहली महिला सीएम मरियम नवाज भी मौजूद थीं। 58 साल की आलिया नीलम पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में दूसरी ऐसी महिला हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस का पद संभाला है। सबसे पहले 2018 में सईदा ताहिरा सदरफ ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद संभाला था।

सुरक्षा अधिकारियों की हाईलेवल मीटिंग खत्म

कठुआ(वरुण) (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों द्वारा सेना के एक गश्ती दल पर घात लगाकर किए गए हमले के कुछ दिनों बाद गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक उच्च स्तरीय अंतरराज्यीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में बी.एस.एफ. और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एकत्र हुए। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा करने और किसी भी तरह की खामियों को दूर करने के लिए बैठक में जम्मू-कश्मीर के डी.जी.पी. आर.आर. स्वैन, पंजाब डी.जी.पी. गौरव यादव और बी.एस.एफ., पश्चिमी कमान के विशेष महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया समेत अन्य लोग शामिल हुए। सोमवार को कठुआ जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर बदनोटा गांव के पास माचेडी-किंडली-मल्हार पहाड़ी मार्ग पर सेना के दो वाहनों पर आतंकवादियों की गोलीबारी में एक जूनियर कमीशंड अधिकारी सहित 5 सैन्यकर्मी मारे गए और कई घायल हो गए।

इस बारे में जानकारी देते अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) जम्मू-कश्मीर, विजय कुमार, ए.डी.जी. (कानून एवं व्यवस्था) पंजाब, अर्पित शुक्ला और पंजाब और जम्मू के महानिरीक्षक रैंक के बी.एस.एफ. अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

चुगलखोर लोगों की वजह से कमजोर है कांग्रेस, उदित राज ने दिल्ली में पार्टी को कमजोर बताया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली कांग्रेस के अधिकतर नेताओं को चुगलखोर बताते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली कांग्रेस में नेतृत्व में बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कमजोर है। जब उदित राज से पूछा गया कि क्या कांग्रेस भविष्य में एपीपी के साथ गठबंधन करेगी तो उन्होंने कहा, भविष्य में क्या होगा, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमारी प्राथमिकता लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। राजनीति में कुछ भी स्थाई नहीं है। सभी निर्णय पार्टी के हाईकमान द्वारा लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे मांग उठाई कि दिल्ली में लगातार हार रहे नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता रहते हैं, वहां कांग्रेस की लगातार हार पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मुझे बुरा लगता है कि पार्टी दिल्ली में अपने (कांग्रेस के) लोगों की वजह से कमजोर है। इन चुगलखोर लोगों की वजह से पार्टी में धूम मची हुई है। ये काम नहीं करते और जो काम करने लगता है उसको सब घेर लेते हैं और काम करने नहीं देते। उन्होंने कहा, ''दिल्ली कांग्रेस में नेतृत्व में बड़े बदलाव की जरूरत है।'' उदित राज ने आगे कहा कि 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के उम्मीदवारों को अधिक से अधिक टिकट दिए जाने चाहिए।

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 13 मछुआरों को किया गिरफ्तार

कोलबों (एजेंसी)। श्रीलंकाई नौसेना ने डेल्फ्ट द्वीप के पास अपने जल क्षेत्र में अवैध शिकार में शामिल होने के आरोप में गुरुवार को तमिलनाडु के 13 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी मछली पकड़ने वाली 3 नौकाएं जब्त कर ली। तमिलनाडु के मत्स्य पालन अधिकारियों ने यहां बताया कि पुडुकोट्टई जिले के रहने वाले मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के करीब गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान श्रीलंकाई समुद्री बलों ने हिरासत में ले लिया। इस बीच, श्रीलंकाई नौसेना ने एक बयान में दावा किया कि वे विदेशी मछली पकड़ने वाले नौकाओं को अवैध तरीके से मछली पकड़ने से रोकने के लिए नियमित गश्त और अभियान चलाते हैं। विशेष अभियानों के हिस्से के रूप में, उत्तरी नौसेना कमान ने भारतीय नौकाओं के एक समूह को खदेड़ने के लिए फास्ट अटैक क्राफ्ट को तैनात किया, जिसके परिणामस्वरूप 13 मछुआरों को

पकड़ लिया गया और तीन भारतीय नौकाओं को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार भारतीय मछुआरों और जब्त की गयी नौकाओं को कांकेसंतुरई बंदरगाह ले जाया गया, जहां उन्हें कानूनी कार्यवाही के लिए मत्स्य अधिकारियों को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि श्रीलंकाई नौसेना ने इस वर्ष अब तक 252 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और कुल 345 भारतीय नौकाएं जब्त की हैं।

ग्वालियर में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर , एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत

ग्वालियर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। ग्वालियर में पुरानी छावनी क्षेत्र में हाईवे पर ऑटो में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, इस हादसे में ऑटो सवार नरेश उनकी पत्नी उषा बेटा राहुल और भतीजी अंकिता की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी लोग मुरैना जिले के रहने वाले थे ऑटो ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। नरेश और उनका परिवार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भिंड गए थे और वहां से लौट रहे थे, गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अभी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है

रुपौली की जनता ने जेडीयू को नकारा, पप्पू यादव बोले- कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी, मैं वहां खड़ा रहूंगा

पटना (एजेंसी)। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने जदयू पर हमला करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया है पप्पू यादव ने कहा कि मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है...मेरे जीवन पर आम आदमी और गरीब का अधिकार है मैं वही करता हूं जो समाज को अच्छा लगता है। रुपौली अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का इलाका है। 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया। ये 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों है?...कांग्रेस की विचारधारा जहां खड़ी रहेगी वहां पप्पू यादव खड़ा रहेगा। मेरा मानना है कि रुपौली की जनता ने जदयू को नकार दिया है।

मणिपुर आज भी बंटा हुआ है, प्रधानमंत्री राज्य का दौरा कर शांति की अपील करें-राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ''मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह दो टुकड़ों में बंटा हुआ है%%, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस% (इंडिया) के घटक दल

मणिपुर में शांति की ज़रूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर, सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। राहुल गांधी ने गत सोमवार को मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। उन्होंने अपने इस दौरे का एक वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स% पर साझा किया। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में मणिपुर का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया, ''मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद, मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूं, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है।

गौतम गंभीर को कोच बनाने से पहले बीसीसीआई ने नहीं ली विराट कोहली से सलाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने से पहले बीसीसीआई ने विराट कोहली से सलाह नहीं ली थी। गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह टीम इंडिया के हेड को बने हैं। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के साथ समाप्त हुआ। उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने पिछले एक साल में तीन आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल खेले जिसमें एक में भारत जीता तो दो हारे। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच रिश्तों में उतार-चढ़ाव की स्थिति है। आईपीएल 2024 के दौरान दोनों के बीच सबकुछ अच्छा होता दिखा था। दोनों गले भी मिले लेकिन अतीती में वे कई बार तीखी बहस में शामिल रहे और ये अनुमान लगाया गया कि कोहली नए मुख्य कोच के चयन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, हालांकि, जब बोर्ड ने गौतम गंभीर को नियुक्त किया तो ऐसा नहीं था। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस दौरान टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025, टी20 वर्ल्ड कप 2026, वनडे वर्ल्ड कप 2027 और डब्ल्यूटीसी 2025-2027 सहित पांच आईसीसी इवेंट खेलेगी। विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट के सबससे छोटे फॉर्मेट से तो संन्यास की घोषणा कर दी है, मगर वह वनडे फॉर्मेट कम से कम 2027 वर्ल्ड कप तो जरूर खेलेंगे। भविष्य को ध्यान में रखते हुए, बीसीसीआई ने कोहली से सलाह किए बिना गंभीर की नियुक्ति पर फैसला किया। बीसीसीआई के एक सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स को इस बात की पुष्टि की। बीसीसीआई सूत्र ने कहा कि, दोनों के बीच बातचीत के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन बोर्ड के लिए बड़ी तस्वीर देखना अहम है, क्योंकि आने वाले सालों में कई युवा खिलाड़ियों के खेलने की संभावना है। वहीं रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि, हार्दिक पंड्या उन कुछ खिलाड़ियों में से एक थे जिनकी राय बोर्ड ने गंभीर को भारत का मुख्य कोच नियुक्त करने से पहले ली थी। रोहित शर्मा के टी20 से रिटायरमेंट लेने के बाद संभावनाएं हैं कि हार्दिक पंड्या को इस फॉर्मेट में टी का कप्तान बनाया जा सकता है।

एक बार फिर विवादों में रियान पराग

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेटर रियान पराग कुछ दिनों पहले अपनी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री के कारण विवादों में घिर गए थे। वह मामला अभी शांत पड़ा ही था कि अब रियान पराग यूट्यूबर मैक्सटर्न के साथ विवादों में आ गए हैं। मैक्सटर्न, जिसका असली नाम सागर ठाकुर है, ये मामला इतना बढ़ गया कि पराग ने मैक्सटर्न को ब्लॉक कर दिया है। मैक्सटर्न नाम के यूट्यूबर ने रियान पराग को एक वीडियो में टैग किया। ये वीडियो अनंत अंबानी के शादी समारोह से लिया गया है, जिसमें सारा अली खान और अनन्या पांडे साथ डांस करती दिख रही हैं। मैक्सटर्न ने पराग को टैग करते हुए लिखा कि, देख भाई इसको। भारतीय क्रिकेटर ने इस यूट्यूबर को मैसेज करके पूछा कि सब कुछ ठीक तो है ना, वहीं मैक्सटर्न ने जवाब में वॉइस मैसेज करते हुए बोला कि उन्होंने पराग को सिर्फ एक मीम में टैग किया था और कोई कमेंट नहीं किया है। बस फिर क्या था, रियान पराग ने मैक्सटर्न को तुरंत ब्लॉक कर दिया। बता दें कि, रियान पराग ने हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में डेब्यू किया, लेकिन 3 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर वह आउट हो गए थे। दूसरे मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाई जबकि तीसरे मैच में उनको टीम में जगह ही नहीं मिली। पराग ने इस बीच दूसरे मुकाबले में एक ओवर लेग स्पिन गेंदबाजी भी की जिसमें उन्होंने 5 रन दिए थे।

युजवेंद्र चहल को हरियाणा सरकार ने किया सम्मानित

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय टम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 7 रन से मात दी और 17 साल के लंबे इंतजार के बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉपी अपने नाम की। चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अलग-अलग राज्यों में सीएम नायब द्वारा सम्मानित किया गया। इस बीच भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को 11 जुलाई 2024 को गुरुग्राम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह से सम्मान मिला। उन्होंने चहल को एक खास तोहफ दिया है। दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। 29 जून को बराबाडोस की सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया था। स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे थे, जिसके चलते उन्हें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्मान किया है। सीएम नायब सिंह गुरुग्राम दौरे पर है, जहां उनसे मिलने चहल अपने परिवार के साथ पहुंचे थे।

चहल हरियाणा के जिंद से आते हैं। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन टीम का हिस्सा होने के चलते सीएम से सम्मान मिला। न्यूज एजेंसी एएनआई ने उनकी वीडियो शेयर की, जिसमें सीएम ने चहल को पहले वर्ल्ड कप विजेता का मेडल पहनाया और फिर शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया।

शाहीन अफरीदी ने कोचों के साथ टी20 वर्ल्ड कप के दौरान की थी बदसलूकी!

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मेन इन ग्रीन के कोचों के साथ दुर्व्यवहार किया। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचों और प्रबंधन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया गया। इस बात की जांच चल रही है कि प्रबंधन कर्मचारियों ने 24 वर्षीय खिलाड़ी के अनुचित व्यवहार के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कोचों के साथ अफरीदी के दुर्व्यहार की खबर तब सामने आई जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा गठित राष्ट्रीय चयन समिति से हटाए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी। बुधवार को पीसीबी ने पुष्टि की है कि, उन्होंने अब्दुल रज्जाक और वहाब रियाज को सूचित कर दिया है कि राष्ट्रीय चयन समिति में अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। अब्दुल रज्जाक पुरुष और महिला चयन समितियों का हिस्सा थे।। जबकि वहाब पुरुष टीम के चयनकर्ता थे। पीसीबी का ये बयान हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पाकिस्तान टीम के जल्दी बाहर होने के बाद आया है, जहां टीम अमेरिका और भारत के खिलाफ मुकाबले में हार कर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। समिति से हटाए जाने के बाद रियाज ने एक्स पर एक पत्र शेयर किया।

पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बाबर आज़म को लिया आड़े हाथ, कहा काफी मौके मिल चुके है उन्हें

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व हरफनमौला शाहिद अफरीदी ने टी20 विश्व कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद आलोचना झेल रहे कप्तान बाबर आजम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें काफी मौके दिये जा चुके हैं और अब पीसीबी को उनकी कप्तानी को लेकर फैसला लेना चाहिये। पूर्व चैम्पियन पाकिस्तान को टी20 विश्व कप में अमेरिका और भारत ने हराकर ग्रुप चरण से ही बाहर कर दिया। वर्ल्ड लीजैंड्स चैम्पियनशिप में भाग लेने बर्मिंघम गए अफरीदी ने वहां मीडिया से कहा ,'' बाबर को पाकिस्तान की कप्तानी के पूरे मौके दिये गए। उसे बतौर कप्तान अपनी उपयोगिता साबित करने का काफी समय मिला। अब पीसीबी जो भी आत्ममंथन करना चाहे, उसे फैसला लेना होगा।'' उन्होंने कहा ,'' मैं भी पाकिस्तान का कप्तान रह चुका हूं और यूनिस खान तथा मिसबाह उल हक भी। लेकिन जब भी टीम ने विश्व कप में खराब प्रदर्शन किया है , पहली छुरी कप्तान पर चली है।'' बाबर चार विश्व कप और दो एशिया कप में टीम की कप्तानी कर चुके हैं। अफरीदी ने यह भी कहा कि पीसीबी अगर नया कप्तान नियुक्त करता है तो दो नये विदेशी कोचों गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी के साथ उसे समय दिया जाना चाहिये। पूर्व कप्तान ने वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक को चयनकर्ता के पद से हटाने के बोर्ड के फैसले पर भी असहमति जताई। उन्होंने कहा ,'' इसका कोई तुक नहीं था। दो चयनकर्ताओं को हटाने से क्या होगा।'' अफरीदी के दामाद शाहीन शाह अफरीदी भी विवादों के घेरे में आ गए हैं क्योंकि एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि वह विश्व कप के दौरान अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। चैनल ने दावा किया कि कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शाहीन टीम प्रबंधन के साथ सहयोग नहीं कर रहा था और टीम में अनुशासन नहीं था।

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल' से पहले सौरव गांगुली ने खरीदी कोलकाता रॉयल टाइगर्स टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने इस साल अगस्त और सितंबर के बीच होने वाले 'इंडियन रेसिंग फेस्टिवल' 2024 में कोलकाता रॉयल टाइगर्स टीम खरीदी। कोलकाता की रेसिंग टीम इस प्रतियोगिता में पदार्पण करेगी जिसमें हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, कोच्चि और अहमदाबाद की सात टीमें भी इसमें हिस्सा लेंगी। 'इंडियन रेसिंग फेस्टिवल' में दो मुख्य चैम्पियनशिप होंगी जो इंडियन रेसिंग लीग और फॉर्मूला 4 इंडियन चैम्पियनशिप हैं। इस जुड़ाव पर उत्साह से भरे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख गांगुली ने कहा, ''मैं 'इंडियन रेसिंग फेस्टिवल' में कोलकाता की टीम के साथ इस यात्रा को शुरू कर काफी उत्साहित हूं। मोटरस्पोर्ट हमेशा ही मेरा जुनून रहा है और कोलकाता रॉयल टाइगर्स के साथ हमारा उद्देश्य 'इंडियन रेसिंग फेस्टिवल' में एक मजबूत विरासत बनाने के साथ नयी पीढ़ी को प्रेरित करना है।'' रेसिंग प्रोमोशंस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अखिलेश रेड्डी ने गांगुली का स्वागत किया। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल में अमेरिका गैम्बिट्स में हिस्सेदारी हासिल की जो वैश्विक शतरंज लीग के दूसरे चरण में हिस्सा लेगी।

जेम्स एंडरसन ने इस भारतीय दिग्गज को बताया सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे हैं। क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले इस इंग्लिश तेज गेंदबाज से जब उनका सामना करने वाले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यहा ना तो विराट कोहली का नाम लिया और ना ही स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का। बल्किन उन्होंने अपने 21 साल के लंबे करियर में सचिन तेंदुलकर को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया है। जिनके खिलाफ वह खेले हैं। इसी महीने 42 साल के होने वाले जेम्स एंडरसन अपने करियर का 188वां टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें वह कुल 701 विकेट चटका चुके हैं।

लॉर्ड्स में अपने विदाई टेस्ट की शुरुआत से पहले स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर एक सवाल-जवाब के सत्र के दौरान एंडरसन ने कहा कि, मुझए लगता है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। बता दें कि, एंडरसन ने भारत के खिलाफ 39 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 149 विकेट झटके हैं। इस दौरान उन्होंने सचिन तेंदुलकर को 9 बार अपना शिकार बनाया। वहीं जिमी से तेज गेंदबाज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ग्लेन मैकग्राथ और डेल स्टेन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैंने जिन गेंदबाजों का सामना किया उनमें से सर्वश्रेष्ठ शायद ग्लेन मैकग्राथ या डेल स्टेन थे। दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल है। दोनों गेंदबाज थोड़े अलग हैं, लेकिन दोनो विश्व स्तरीय हैं।

बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन..., पीसीबी से बर्खास्त किए जाने के बाद वाहब रियाज ने तोड़ी चुप्पी

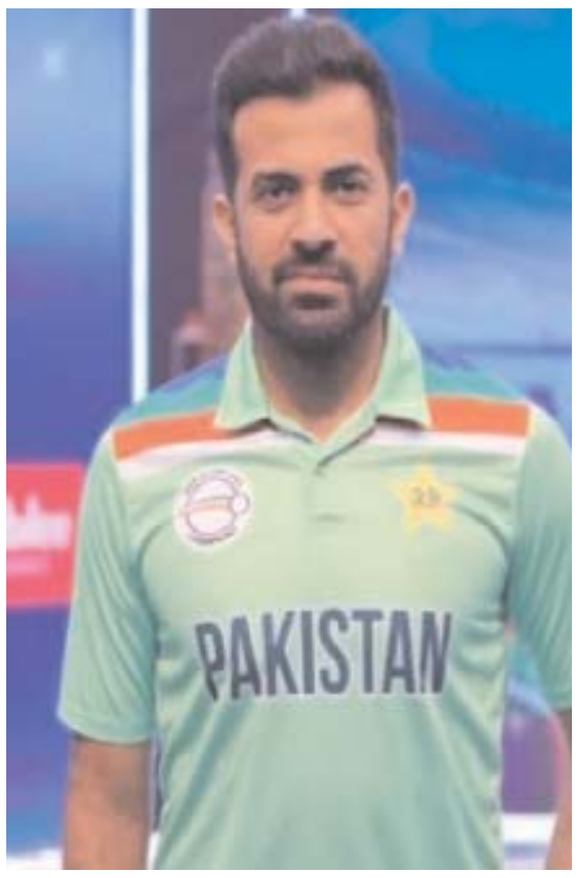

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज को पीसीबी चयन समिति से बर्खास्त किया गया है। टी 20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम के लचर प्रदर्शन के बाद पीसीबी ने ये फैसला लिया। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। ये वहीं, ग्रुप था, जिसमें अमेरिका और कनाडा जैसी डेब्यू टीम शामिल थी। भारत और अमेरिका के खिलाफ मिली हार के साथ ही पाकिस्तान का टूर्नामेंट में सफर खत्म हो गया था। इसके बाद पीसीबी चेयरमैन ने कई इंटरव्यू में रिपोर्ट्स को कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर को बदला जाए और इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2024 से हो गई। पीसीबी ने चयन समिति से वहाब रियाज और अब्दुल रज्जाक को बर्खास्त किया। चयन समिति से बर्खास्त किए जाने के बाद वहाब रियाज का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। दरअसल, वहाब रियाज ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीसीबी के लिए चयन समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने का मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं बस अपने लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने उस खेल की सेवा की है जिसे मैं विश्वास और ईमानदारी से प्यार करता हूं और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरीन के लिए 100 प्रतिशत दिया है। इसके अलावा पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने कहा कि चयन पैनल के हिस्से के रूप में सेवा करना सम्मान की बात है। राष्ट्रीय टीम का चयन करने के लिए सात सदस्यीय पैनल के हिस्से के रूप में निर्णय लेना काफी शानदार रहा। सभी के वोट का महत्व सम्मान था, हमने एक टीम के रूप में चयन निर्णय लिए और उस प्रक्रिया की जिम्मेदारी सम्मान रूप से शेयर की। इसमें अपना योगदान देना सम्मान की बात थी। इस दौरान वहाब रियाज ने ये भी लिखा कि वह कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन वह ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनाना चाहते।

बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा की नि:शुल्क कोचिंग का नया बैच प्रारंभ

समय का सदुपयोग करें, कोचिंग सुविधा का लाभ उठायें-कलेक्टर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बेटियों को पुलिस सेवा में भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नि:शुल्क कोचिंग के नये बैच का शुभारंभ गुरूवार को कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा द्वारा किया गया। कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही बालिकाओं को उपयोगी टिप्स देकर प्रोत्साहित भी किया।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बालिकाओं से कहा कि असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए बल्कि कमियों का आंकलन कर और भी उत्साह से लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा गाइडेन्स मिल जाये तो प्रथम प्रयास में भी सफलता हासिल हो सकती है। जीवन में यह अवस्था और समय सबसे अधिक मेहनत करने का होता है। जितनी अधिक मेहनत की जायेगी उतना ही आपका भविष्य सुखमय होगा और उत्कृष्ट जीवन जी सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि कक्षा 12वीं के बाद किसी भी छात्र-छात्रा की कैरियर की दिशा तय होती है। समय का सदुपयोग करे और नि:शुल्क कोचिंग की सुविधाओं का भरपूर लाभ उठायें। कलेक्टर ने कहा कि विगत वर्षों से संचालित बालिकाओं की कोचिंग के बेहतर परिणाम भी मिले हैं। कई प्रतिभागी बालिकाओं का चयन दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश पुलिस और अन्य विभागों के लिए हुआ है। यहां लाइब्रेरी और वाईफाई कनेक्शन की सुविधा भी है। सभी बालिकायें खूब मेहनत कर पिछले सभी बैच से भी बेहतर परिणाम लाने का प्रयास करें। कार्यक्रम को श्रीमती नेहा चौधरी वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह, सहायक संचालक श्याम किशोर द्विवेदी, सीडीपीओ पुनीत शर्मा ने भी संबोधित कर बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास विभाग द्वारा बेटियों को पुलिस की भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वर्ष 2017 से नि:शुल्क कोचिंग क्लास चलाई जा रही है। सत्र 2024-25 के नये बैच के लिए 276 बालिकाओं ने अपने आवेदन प्रस्तुत किये थे। जिसमें स्क्रीनिंग के आधार पर मेरिट में 100 बालिकाओं के बैच का चयन किया गया है। कार्यक्रम के बाद में कलेक्टर अनुराग वर्मा, श्रीमती नेहा चौधरी वर्मा और जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह ने कन्या धवारी स्कूल के पास जिला बाल संरक्षण इकाई में संचालित नि:शुल्क कोचिंग परिसर में एक पेड़ बेटी के नाम बालिकाओं के साथ पौधे भी रोपे।

उप मुख्यमंत्री ने किये मां शारदा देवी के दर्शन

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने अपने मैहर प्रवास के दौरान गुरूवार को मैहर पहुंचकर त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा देवी के दर्शन किये और उनकी पूजा-अर्चना की। इस दौरान विधायक मैहर श्रीकांत चतुर्वेदी, कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया पौध रोपण

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा मैहर मां शारदा दर्शन के मंदिर परिसर के पास पुलिस लाइन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर विधायक मैहर श्रीकांत चतुर्वेदी, कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य उपस्थित रहे।

मैहर जिले में क्लस्टर पंचायतों में लगेंगे समस्या निवारण शिविर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मैहर जिले में राजस्व एवं अन्य समस्त विभागों से संबंधित मैदानी स्तर पर लंबित कार्यों, शिकायतों एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए तीनों विकासखण्ड की क्लस्टर ग्राम पंचायतों में शिविर लगाये जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मैहर श्रीमती रानी बाटड द्वारा जारी आदेशानुसार इन शिविरों के लिए संबंधित एसडीएम नोडल अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

कलेक्टर मैहर के आदेशानुसार क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के ग्रामीण जन अपनी समस्यायें बता सकेंगे। शिविर में जिला स्तरीय और विकासखण्ड स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्य संपादित करेंगे। नोडल अधिकारी सभी विभागों से समन्वय कर शिविर में आने वाले आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे और रिकार्ड संधारित करेंगे। यह शिविर क्लस्टर मुख्यालय की ग्राम पंचायत के भवन में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित तिथि को आयोजित होंगे।

शिविर के निर्धारित कार्यक्रम मानुसार मैहर तहसील में 18 जुलाई को पकरिया, 25 जुलाई को अमदरा, 1 अगस्त को कुसेड़ी, 8 अगस्त को पोड़ी, 15 अगस्त को गोबरी, 22 अगस्त को नादन शारदा प्रसाद, 29 अगस्त को तिलौरा, 5 सितंबर रिवारा, 12 सितंबर को सोनवारी, 19 सितंबर को बदेरा क्लस्टर पंचायत में शिविर आयोजित होंगे। तहसील अमरपाटन में 19 जुलाई को परसवाही, 26 जुलाई को बेला, 2 अगस्त को रामगढ़, 9 अगस्त को ताला, 16 अगस्त को मौहारी कटरा तथा 26 अगस्त को लालपुर ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित होंगे। इसी प्रकार रामनगर तहसील में 22 जुलाई को मूर्तिहाई, 29 जुलाई को जिगना, 5 अगस्त को गंगासागर, 12 अगस्त को गोरसरी तथा 2 सितंबर को बड़ाइटमा ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे।

स्मार्ट सिटी के 369 करोड़ लागत के 48 कार्य पूर्ण, 24 कार्य प्रगति पर, कलेक्टर ने की समीक्षा

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के 369 करोड़ लागत के 48 प्रोजेक्ट वर्क पूरे कर लिये गये हैं जबकि 545 करोड़ 86 लाख रूपये लागत के 24 कार्य प्रगति पर है। स्मार्ट सिटी के 915 करोड़ लागत से कुल 72 कार्य स्वीकृत है। इस आशय की जानकारी गुरूवार को कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्मार्ट सिटी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में दी गई। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना सहित नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी तथा कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सतना स्मार्ट सिटी के पूर्ण हुए 48 कार्यों की नीचे के ₹ म से कलेक्टर ने समीक्षा प्रारंभ की। उन्होंने दादा सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम, नगर निगम व्हीकल यार्ड, जीआई एस बेस्ट प्रापर्टी टैक्स रजिस्टर, नेक्टर झील जैसे अनेक प्रोजेक्ट वर्क में फिनिशिंग कार्य शेष रहने के बाद उन्हें पूरा बताये जाने पर अप्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने कहा कि फिनिशिंग कार्यों को ओ एण्ड एम के लिये नहीं छोडे। किसी भी प्रोजेक्ट वर्क में फाइनल फिनिशिंग के शेष रहते कार्य को पूरा नहीं माना जायेगा। पूर्ण बताये जा रहे कार्यों का आयुक्त नगर निगम स्वतः एक बार निरीक्षण कर पूर्णता की स्थिति बतायेंगे। कलेक्टर ने विजुअल एम्प्रूवमेंट और रीवा-सतना-पन्ना मार्ग के डिवाइडर कार्य तथा इंटर स्टेट बस टर्मिनल के कार्य पर संविदाकार एजेंसी एबीसी पर गहरी नाराजगी प्रकट की। कलेक्टर ने कहा कि स्थानीय कार्यकारी एजेंसी को अपने शहर को सुन्दर और स्मार्ट बनाने के लिए स्व प्रेरणा से भी अच्छा काम करना चाहिए।

कलेक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट इंजीनियरों की प्रजेन्स कार्य स्थल फील्ड में दिखनी चाहिए। उनके लिए अब आफिस का काम शेष नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में गुणवत्ता और स्मार्ट नेस भी दिखनी चाहिए। अगली बैठक तक ग्राउण्ड पर स्मार्ट सिटी के काम दिखने चाहिए। कमिश्नर नगर निगम से उन्होंने इंजीनियर को दैनिक टास्क देने, उनकी ग्राउण्ड में उपस्थिति सुनिश्चित करने और सतत मानीटरिंग करने को कहा है। नेक्टर झील में बम्बू रेस्टोरेन्ट की संरचना और व्यंकटेश लोक में बॉली बाल कोर्ट का पार्ट बिना बोर्ड की जानकारी में लाये हटाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के प्लान और एसओपी के तहत ही कार्य पूर्ण किये जाये।

विजुअल इम्प्रूवेमेंट नारायण तालाब का कार्य पूर्ण नहीं कर पाने संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी कर निविदा टर्मिनेट करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इंटर स्टेट बस टर्मिनल में गुणवत्ता के अभाव और हो रही देरी पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। साइकल ट्रेक की उपयोगिता की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि सायकलिंग के लिए इसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने आयुक्त नगर निगम स्वयं मानीटरिंग करें।

सीवर लाइन के रेस्टोरेशन कार्य की डेली रिपोर्ट करें

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सतना नगर निगम में अमृत परियोजना के तहत सीवर लाइन प्रोजेक्ट वन और टू के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन के चल रहे कार्य से आम जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट के नार्म्स के अनुसार खुदाई और रोड रेस्टोरेशन का कार्य करें। रोड रेस्टोरेशन में रोलर के माध्यम से लेयर काम्पेक्सन होना चाहिए। नगर निगम के जिस क्षेत्र में खुदाई का काम ज्यादा हो वहॉ उपयंत्री को साइट बांट कर निरंतर मानीटरिंग करायें। कलेक्टर ने कहा कि पीडीएमसी यदि एजेंसी से नार्म का पालन नहीं करा पा रही तो उस पर भी पेनाल्टी लगाये। प्रोजेक्ट वन और टू दोनों कान्ट्रेक्टर और पीडीएमसी के अधिकारी शहर में कहां क्या काम चल रहा है। दैनिक स्थिति को वाट्सअप ग्रुप में अपडेट करेंगे। प्रोजेक्ट वन के तहत सीवर की 162131 मीटर लेइंग कम्पलीट कर ली गई है। जिसमें 4754 मीटर लेइंग शेष है। रोड रेस्टोरेशन 157717 मीटर में पूर्ण किया जा चुका है जबकि 4414 मीटर में रोड रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। प्रोजेक्ट का कार्य 97.27 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

सीवर लाइन प्रोजेक्ट 2 की समीक्षा में बताया गया कि सतना शहर में विभिन्न वार्डों में 190081 मीटर लाइन लेइंग कम्पलीट कर ली गई है जबकि 112248 मीटर लेइंग शेष है। रोड रेस्टोरेशन का कार्य 176069 मीटर पूरा कर लिया है। जबकि 14012 मीटर रोड रेस्टोरेशन का कार्य शेष है। कलेक्टर ने कहा कि बरसात में घनी बस्तियों और सकरी गलियों में खुदाई का कार्य नहीं करें। कार्य ऐसा करें जिससे लोगों को दिक्कतें नहीं हो। कलेक्टर ने काम्पेक्सन का काम शीघ्र पूरा करने और सुरक्षित तरीके से खुदाई क्षेत्र में कार्य में संलग्न लोगों को ही जाने की इजाजत देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बरसात में सीवर कार्य की वजह से कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए।

एक साथ 5 हजार पौधे लगाने की योजना बनायें-कलेक्टर

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नगर निगम सतना के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के शेष थोड़े आवास भी कम्पलीट करने के निर्देश दिये। योजना में स्वीकृत 4209 आवासों में से 3888 पूर्ण कर लिये गये हैं। बताया गया कि सतना नदी पर जिगनहट में एनीकेट निर्माण का 38.22 करोड़ रूपये का डीपीआर भेजा गया है। सम्पत्ति कर में गत वर्ष नगर निगम द्वारा 6.20 प्रतिशत की वसूली की थी। चालू वर्ष में अब तक 4.11 प्रतिशत की वसूली की गई है। नगर निगम की वृक्षारोपण की कार्य योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि पूरे वर्षा काल में केवल 5 हजार पौधे लगाने की कार्य योजना का विस्तार करे और नगर निगम के सभी वार्डों और उपयुक्त स्थान पर एक दिन में 5 हजार पौधे लगाने की कार्य योजना बनाये। कलेक्टर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 75 हजार भवन है। एक भवन में 2 पौधे के मान से नगर निगम क्षेत्र में डेढ़ लाख पौधे आम जन के सहयोग से लगाये जा सकते हैं।

मैहर में पुलिस लाइन में किया गया पौध रोपण

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मैहर कलेक्टर रानी बाटड एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल की उपस्थिति में गुरूवार को मैहर जिले के पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती बाटड ने पौधारोपण करने और उसकी रक्षा करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, सीएसपी राजीव पाठक, तहसीलदार जितेंद्र पटेल तथा थाना प्रभारी अनिमेष दिवेदी उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया वृक्षा रोपण

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत गुरुवार को पुलिस लाइन सतना में कलेक्टर अनुराग वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता द्वारा सामूहिक रूप से वृहद वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा ने प्राकृतिक संतुलन में पेड़-पौधों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण कर उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि हर एक व्यक्ति "एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत" एक पौधे का रोपण करे, पौधारोपण करने के बाद उसका संरक्षण करना बेहद जरूरी है। संरक्षण के अभाव में पौधा पेड़ का रूप नहीं ले सकता है, इसलिए उसे पेड़ का रूप देने का संकल्प ले, जिससे कि आने वाले दिनों में आपके द्वारा लगाए गए पेड़ो से पूरा क्षेत्र हरभरा हो जाए। इस अवसर पर नेहा चौधरी वर्मा, पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे। पुलिस लाइन में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने अपने परिवार के जनों के साथ पौधरोपण किया।

नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस शुरू

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। यूपीएससी एवं एमपीपीएससी नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस का नवीन बैच 12 जुलाई को इनक्यूबेशन सेंटर, कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे, धवारी चौराहा पर शुरू होने जा रहा है। यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की तैयारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन का समय प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित है। नि:शुल्क कोचिंग क्लासेस मेंस पर आधारित रहेगी। साथ ही अधिकारियों के भी रहेंगे। कलेक्टर अनुराग वर्मा और आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा नि:शुल्क कोचिंग के परीक्षित भारती के सहयोग से 13 मार्च 2022 से यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की नि:शुल्क कोचिंग सतना में निरंतर संचालित हो रही है।

सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कैरियर मार्गदर्शन

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। प्रदेश के सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये कैरियर मार्गदर्शन होगा। इसके लिये नोडल शिक्षकों को वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई है। वर्तमान में विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट के लिये यू-रिपोर्ट के माध्यम से लाईव-11 कोर्स का उपयोग प्रदेश के सीएम राइज और पीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थी उपयोग कर रहे हैं। कैरियर मार्गदर्शन का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय की समझ एवं कैरियर के महत्व को समझाना और कक्षा 10वीं के बाद विषय संबंधित निर्णय लेने में सहायक बनाना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कैरियर के बारे में जानकारी दी जायेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आगे चलकर स्वयं का व्यवसाय और उद्यमशीलता के बारे में जानकारी दी जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि इसके लिये वे संबंधित विद्यालयों में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाये। वेबिनार में विद्यार्थी अपनी शंका का समाधान और जिज्ञासा चैट में प्रश्न कर सकते हैं।

प्रदेश के 4473 विद्यालयों में नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 कक्षाओं का होगा संचालन

प्रदेश के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन ऐसे विद्यालयों में किया जायेगा जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है। प्रदेश में 4473 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। जहाँ कक्षा एक से 12, एक से 10वीं, एक से 8वीं और एक से पाँचवी के विद्यालय हैं, जिनके परिसर में आंगनवाड़ी संचालित नहीं है। ऐसे विद्यालयों में नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 का संचालन किया जायेगा। इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी को शाला सत्यापन के साथ इनके प्रमाणीकरण के लिये भी कहा गया है।

डायबिटीज से बचाव और उपचार के लिए एडवाइजरी जारी

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण सामान्य होते हैं पर यह धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। यह बीमारी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी फूड खाने एवं आनुवांशिक भी होती है। धीरे-धीरे मधुमेह के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इसे जन जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह की सही समय पर पहचान उसके उपचार एवं जन जागरूकता के मध्यम से मधुमेह रोगियो की स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा सकता हे। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मधुमेह के उपचार के लिए असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों को नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। बार-बार पेशाब आना, वजन का घटना या भूखा कम लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, कमजोरी अथवा थकान होना इत्यादि मधुमेह के मुख्य लक्षण है। मधुमेह की रोकथाम के लिए शरीर के वजन को सामान्य बनाए रखना, पौष्टिक आहार का सेवन, नियमित व्यायाम, चलना अथवा दौड़ना जैसी गतिविधियां करना, नशीले पदार्थों तंबाकू एवं शराब का सेवन नहीं करना महत्वपूर्ण है। मधुमेह के जांच एवं उपचार की नि:शुल्क सुविधा सभी हेल्थ एंड वैलनेस केंद्रों पर भी उपलब्ध कराई गई है। जिससे कि मरीजों को नियमित रूप से दवाओं की प्राप्ति एवं फॉलो किया जा सके एवं उन्हें दूर के चिकित्सालय तक इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। मधुमेह के साथ सामान्य जीवन बताया जा सकता है। मधुमेह की नियमित रूप से जांच कराये जाना बेहद आवश्यक है जिससे कि मधुमेह की पड़ताल एवं उसकी प्रारंभिक अवस्था में उपचार हो सके।

निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मैहर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड ने जिले में संचालित सीमेंट फैक्ट्रियों के द्वारा सीएसआर मद से किए गए निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केजेएस, अल्ट्राटेक तथा एमपी बिरला सीमेंट के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।